नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 51 | नोएडा, शनिवार, 21 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

मनुष्य को चाहिए कि वह जिस स्थिति में भी हो, मृत्यु की परवाह न करके कर्तव्य का पालन करे। मृत्यु की अपेक्षा अधर्म से अधिक डरना चाहिए।

सुकरात



ऑपरेशन सिंदूर के बाद | पाकिस्तानी मंत्री पहली बार भारत पहुंचे

आज शंघाई सहयोग संगठन फोरम में लेंगे हिस्सा; पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 25 देशों को न्योता भेजा



नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई मंत्री शुक्रवार को भारत पहुंचे। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल हुए। वे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के पुराना किला में फोरम का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम 22 नवंबर तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं।

भारत ने इस फोरम के लिए 25 देशों को न्योता भेजा था, जिनमें से 15 ने भागीदारी की पुष्टि की है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की साझा सभ्यता और संस्कृति को सामने लाना और उनके बीच आपसी बातचीत बढ़ाना है।

पाकिस्तान ने संस्कृति मंत्री की जगह जलवायु मंत्री को भेजा- भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को फोरम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। हालांकि, पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया।

1 रुपये किराये पर जमीन, टैक्स में भी छूट

गुजरात की नई वेस्ट-टू-एनर्जी नीति में निवेशकों को राहत का प्रस्ताव



गांधीनगर (एजेंसी)। गुजरात सरकार नगरपालिका के ठोस कचरे से बिजली बनाने वाली परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई वेस्ट-टू-एनर्जी नीति-2026 तैयार कर रही है। इस प्रस्तावित नीति में कंपनियों को कई वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके तहत परियोजना डेवलपर्स को 30 साल तक मात्र 1 रुपये सालाना के किराये पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। साथ ही, परियोजना स्थल पर नगरपालिका का ठोस कचरा भी मुफ्त दिया जाएगा।

कचरे से बिजली बनाने वाली परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा- नई नीति का उद्देश्य लैंडफिल पर निर्भरता कम करना और कचरे को खुले में फेंकने या जलाने की समस्या पर रोक लगाना है।

राहुल गांधी को सुनकर खुशी हुई

कांग्रेस नेता के बयान पर गदगद हुए पूर्व इजरायली राजनयिक, बताया बेहद खास

नईदिल्ली/तेल अवीव(एजेंसी)। राहुल गांधी के इजरायल-भारत के संबंधों पर दिए बयान की डैनियल कार्मोन ने तारीफ की है। भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत कार्मोन ने कहा है कि गांधी ने सार्वजनिक मंच से दोनों देशों के बेहतर रिश्ते पर जो बातें कही हैं, वह उनके मुल्क के लिए काफी अहमियत रखती हैं। राहुल गांधी के इजरायल-भारत की साझेदारी को मान्यता देने पर यकीनन मुझे खुशी हुई है। राहुल ने भारत-



इजरायल के अच्छे संबंधों पर जोर दिया है, जिसके बाद कार्मोन का ये बयान आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका के शिकागो में कहा है कि भारत को इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए। राहुल ने गाजा में इजरायली हमलों को गलत कहा लेकिन ये भी माना कि इजरायल से रिश्ते वक्त की जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति देश के हितों को देखते हुए तय की जानी चाहिए।

डैनियल कार्मोन ने क्या कहा है

डैनियल कार्मोन ने एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया है। इसमें वह कह रहे हैं, मैं इजरायल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थक हूं। हमारे रणनीतिक हित हैं, जिनमें सेना के लिए हथियार खरीद भी शामिल है। मैं 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा में इजरायल की कार्रवाई, दोनों की निंदा करता हूं। एक गलत काम को दूसरे गलत से सही नहीं होता है। भारत को उन बातों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, जिनमें वह विश्वास रखता है। शिकागो यूनिवर्सिटी में अपनी बातचीत में राहुल गांधी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्तों का खुलकर समर्थन किया है।

योगी आदित्यनाथ की मां का निधन

91 साल की थीं, पौड़ी गढ़वाल में अपने घर में ली अंतिम सांस; आज ऋषिकेश में अंतिम संस्कार

देहरादून (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 91 साल की थीं। सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पौड़ी गढ़वाल ने पंचूर गांव में सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। उस वक्त घर में योगी के भाई महेंद्र और उनका परिवार मौजूद था। योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे तक पंचूर गांव पहुंच सकते हैं। एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया कि आज ऋषिकेश के संपूर्णानंद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। जिस वक्त सावित्री देवी का विधन हुआ उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सशक्त युवा, समृद्ध उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।



बगैर ठोस वजह पत्नी अलग, गुजारा भत्ते की हकदार नहीं

हिमाचल हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा; कहा- बेटे का खर्च उठाना होगा



शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में साफ किया है कि पत्नी यदि बिना पर्याप्त और उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।

जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जसवाल की बेंच ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

हालांकि, नाबालिग बेटे को हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश जारी रहेगा। पति को उसकी पढ़ाई, इलाज और शादी का खर्च भी उठाना होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला 17 नवंबर 2026 को सुनाया।

2021 में शुरू हुआ था भरण-पोषण का मामला- पुष्पा देवी और सुनील कुमार के बीच भरण-पोषण को लेकर कानूनी विवाद 2021 में शुरू हुआ था। बिलासपुर फैमिली कोर्ट में यह मामला केस नंबर 14/04/2021 के तहत दर्ज हुआ। फैमिली कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

एमए-बीएड शिक्षित पत्नी ने गुस्से में मारपीट की बात मानी- मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि पत्नी एमए और बीएड शिक्षित है। रिकॉर्ड के अनुसार, उसने अपनी गवाही में स्वीकार किया था कि उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वह पति के साथ मारपीट करती थी। पति ने भी पत्नी के आक्रामक व्यवहार और मारपीट को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई थीं। दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत स्तर पर समझौते भी हुए थे। हालांकि, पत्नी पति से अलग रहने की कोई पर्याप्त वजह अदालत में साबित नहीं कर पाई।

पत्नी ने कहा- कमाई का कोई साधन नहीं

पत्नी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए उसे पति से भरण-पोषण मिलना चाहिए। उसने पति पर मारपीट और क्रूरता के आरोप भी लगाए।

वहीं, पति सुनील कुमार ने कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की, जिसके कारण पत्नी को घर छोड़ना पड़े। पति आईटीआई में क्लर्क है और उसकी मासिक सैलरी 46 हजार रुपए बताई गई है।

चक्रवात अकवान

आंध्र प्रदेश-ओडिशा के तट से टकराया

90 किमी की रफ्तार से हवाएं चल रहीं; ओडिशा-आंध्र में भारी बारिश, 4 लाख लोग शिफ्ट



भुवनेश्वर/विशाखापट्टनम (एजेंसी)। चक्रवाती तूफान अकवान शुक्रवार सुबह करीब 7.30 से 8.30 बजे के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच गोपालपुर तट से टकराया। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 90 किमी चल रही। तूफान का तट से टकराना अभी भी जारी है।

तूफान के असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा में करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इनके लिए 9,341 राहत शिविर बनाए गए हैं। साथ ही 423 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं।

तूफान के चलते पूर्वी रेलवे ने 41 और दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं, 29 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है।

तूफान का असर 10 राज्यों में पड़ सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड में भी मौसम बदल सकता है और बारिश हो सकती है।

ओडिशा : भारी बारिश के बीच बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया

ओडिशा के गंजाम जिले में तारासिंग पुलिस थाने की टीम ने भारी बारिश के बीच घने जंगल और दुर्गम रास्तों से एक बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला।

प. बंगाल : गंगासागर में पर्यटकों को समुद्र तट से हटाया गया- चक्रवात अकवान के असर से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम को देखते हुए गंगासागर में प्रशासन लगातार घोषणाएं कर रहा है और तीर्थयात्रियों व पर्यटकों से समुद्र तट खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है।

बोत्सवाना से आई मादा चीता केओएमजी 3 ने दी गुड न्यूज़

पहली बार चार शावकों को दिया जन्म, अब चीतों की संख्या हुई 62



भोपाल/श्योपुर (एजेंसी)। बोत्सवाना से आई मादा चीता ने भी भारत में गुड न्यूज दी है। अभी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता ही आबादी बढ़ा रही थीं। अब केओएमजी 3 ने गुड न्यूज दी है। उसने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या 62 हो गई है।

पहली बार बोत्सवाना की मादा चीता बनी मां- मोहन यादव ने कहा कि यह मध्यप्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। बोत्सवाना से आई किसी मादा चीता द्वारा भारत में पहली बार शावकों को जन्म देना प्रोजेक्ट चीता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत में चीतों की व्यवहार्य आबादी को पुर्नस्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक कदम है। उन्होंने कहा कि मादा चीता केओएमजी 3 ने चार महीने से अधिक समय जंगल में बिताने के बाद प्राकृतिक परिस्थितियों में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है।

2022 में हुई थी चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत- इसके साथ ही सीएम ने कहा कि साल 2022 में चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद जंगल में शावकों के जन्म की यह दूसरी दर्ज घटना है। चार नए शावकों के जन्म के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है।

सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

सीएम मोहन यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से लाई गई ढाई वर्ष की मादा चीता केओएमजी 3 द्वारा चार स्वस्थ शावकों को जन्म देने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों एवं वनकर्मियों को हार्दिक बधाई दी है।

प्रोजेक्ट चीता से जुड़े कर्मियों की सराहना की

मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रोजेक्ट चीता के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों, अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन सभी के समर्पण, अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

राजस्थान में 6 डिग्री, मप्र में पारा 7 डिग्री पहुंचा

नई दिल्ली/लखनऊ/भोपाल/जयपुर/पटना (एजेंसी)। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में लगातार बर्फबारी जारी है। इसके असर से मैदानी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है।



राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। एमपी में कटनी सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। ठंड के साथ ही कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सुबह घना कोहरा छाया है।

सोना एक साल में सबसे सस्ता

नईदिल्ली (एजेंसी)। सोना-चांदी में लगातार गिरावट जारी है। आईबीजेए के मुताबिक, शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,947 रुपए सस्ता होकर 1.23 लाख रुपए पर आ गया। इस गिरावट के बाद सोना करीब एक साल पुराने स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल 24 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,308 रुपए था। इसके बाद सालभर तक इसके भाव ज्यादा बने रहे। इधर, चांदी के भाव में भी शुक्रवार को 9,789 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद चांदी 1.50 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।





'हमारे देश में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता'

मसूद के बयान पर भड़के किरेन रिजिजू

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में चयन नहीं होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा लगाए गए धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अवसर धर्म के आधार पर नहीं दिए जाते हैं, मेरिट के आधार पर मिलते हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और न ही किसी को नजरअंदाज किया जाता है। अवसर योग्यता और प्रतिभा के आधार पर मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति का धर्म या जाति देखकर न तो उसे कोई काम दिया जाता है और न ही उससे काम छीना जाता है। इस तरह की सोच रखना भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम सब एक हैं और हमारा लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' है। हम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन में विश्वास रखते हैं। फिर, लोगों को जाति या धर्म के आधार पर बांटने की क्या जरूरत है? भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस अब क्रिकेट टीम के चयन में भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिराज को इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि वह मुसलमान हैं। यहां तक कि जडेजा को भी बाहर रखा गया था। हर क्रिकेटर जो जर्सी पहनता है, वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वोट बैंक और सांप्रदायिक



राजनीति के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बांटना बंद करें।

भाजपा नेता बूरा नरसैया गौड़ ने कहा कि मसूद का यह बयान कि मोहम्मद सिराज को उनके नाम की वजह से राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में हमारा मानना है कि हम सब एक हैं। सभी भारतीय एक हैं। हमारे धर्म भले ही अलग हों, लेकिन हमारा डीएनए और हमारा खून एक ही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रदर्शन के आधार पर अन्य खिलाड़ियों को भी बाहर रखा जाता है।

लेकिन, इसे धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। भाजपा नेता अनिकेत निकम ने कहा कि मैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को बस यही सलाह दूंगा कि वे समाज में जहर फैलाना बंद करें। हमारे देश के खिलाड़ी हमारे तिरंगे के नाम पर खेलते हैं। वे हमारे देश के लिए खेलते हैं, न कि किसी समुदाय, धर्म या जाति के नाम पर। उनका चयन भी इस आधार पर नहीं होता कि वे किस समुदाय, जाति या धर्म से आते हैं। उनका चयन इस आधार पर होता है कि वे कैसा खेलते हैं। इसलिए, मसूद समाज में जो बंटवारा पैदा करने का काम कर रहे हैं, उसे बंद कर देना चाहिए। इससे हमारे समाज की तरक्की नहीं होगी और देश के लोग उनके इस जहर फैलाने वाले काम को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दूसरी ओर, एनसीपी (एसपी) नेता नसीम सिद्दीकी ने इमरान मसूद के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने जो बात रखी है, वह बिल्कुल सही है। इस देश में निश्चित रूप से भेदभाव हो रहा है, यह हमारे देश में हो रहा है। खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। चाहे वे मुस्लिम आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों, नौकरशाह हों, खिलाड़ी हों, संगीतकार हों या प्रोफेसर हों, जीवन के हर क्षेत्र में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए, अगर इमरान मसूद ने यह आशंका जताई है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसी का नाम 'अब्दुल' है, तो वह चाहे कितना भी अच्छा खेले, कहीं न कहीं उसे पीछे रोकने की कोशिश जरूर की जाती है।

जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

जवाबी हलफनामा के लिए एक सप्ताह का समय

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से सर्कुलेट की गई लिखित दलीलों में शामिल कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लिखित दलीलों में शामिल तथ्यों



की सत्यता की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में अपनी लिखित दलीलें सर्कुलेट की हैं। इस पर बेंच ने कहा कि लिखित दलीलें आज ही प्राप्त हुई हैं और इनमें कई तथ्यात्मक बातें शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तथ्यों को हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। मुक्ता गुप्ता ने इस पर कहा कि उनकी दलीलों में कोई तथ्यात्मक दावा नहीं है, बल्कि ये कानूनी दलीलें हैं। उन्होंने बताया कि लिखित जवाब में इस मामले में पहले दिए गए फैसलों और कानून की व्याख्या से जुड़े बिंदु रखे गए हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले पेश होने वाले वकील राजू को कुछ निजी पारिवारिक परेशानियां थीं। चूंकि कई मामलों में उनका नाम दर्ज था, इसलिए उन सभी मामलों में पत्र सर्कुलेट किए गए थे।

बाद में जब उन्हें पता चला कि वह इस मामले में कोर्ट की सहायता कर रहे हैं, तो उन्होंने संबंधित पत्र वापस लेने के लिए कहा। तुषार मेहता ने फिर दोहराया कि लिखित जवाब या रिप्लाई दाखिल करने वाले व्यक्ति को उसमें शामिल तथ्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कावेरी के अतिरिक्त पानी की मांग वाली तमिलनाडु की अर्जी को खारिज किया

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उन अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित किया और कर्नाटक को कावेरी का अधिक पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'हमने (याचिका) खारिज कर दी है।' तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का

कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया कि सीडब्ल्यूएमए और 'कावेरी जल विनियमन समिति' (सीडब्ल्यूआरसी) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच पानी छोड़े जाने और उसके वितरण की निगरानी कर रहे हैं।

दरवाजा खटखटाया था और कावेरी नदी के पानी में अपने हिस्से को तुरंत जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का तर्क था कि पानी की कमी से वहां के किसानों और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। ये याचिकाएं ऐसे समय में दायर की गई थीं, जब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद खासकर बारिश की स्थिति और नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच सामने आया है। कर्नाटक ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया और कहा कि वह 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों का पालन कर रहा है। पड़ोसी राज्य ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, अपने जलाशयों में पानी की आवक में कमी और पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता का भी जिक्र किया।

उपराष्ट्रपति 21 व 22 नवंबर को महाराष्ट्र और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे



नई दिल्ली, 20 नवम्बर (वेब वार्ता)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 21 और 22 नवंबर को महाराष्ट्र और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद चेन्नई में नेल्लई नादर मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के 42वें वार्षिक समारोह में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सीपी राधाकृष्णन 21 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वह चेन्नई जाएंगे। वहां 22 नवंबर को नेल्लई नादर मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के 42वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे।

दिल्ली में 26 नवंबर को लगेगी डाक अदालत, 24 नवंबर तक भेजनी होगी शिकायत

नई दिल्ली। दिल्ली में डाक सेवाओं से जुड़ी लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए 26 नवंबर को सर्किल स्तर की डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें केवल दिल्ली की मंडलीय स्तर की डाक अदालतों में उठाई गई उन शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका अब तक समाधान नहीं हुआ है। डाक विभाग के दिल्ली सर्किल के अनुसार डाक अदालत का आयोजन नई दिल्ली के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास मेघदूत भवन स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय की तीसरी मंजिल पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। डाक विभाग ने कहा कि शिकायतें सहायक निदेशक (सीएस), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, दिल्ली सर्किल, नई दिल्ली 24 नवंबर तक भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22-23 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे



नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 और 23 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 नवंबर को बालेन्द्र शाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को भी दर्शाती है। यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा पारस्परिक लाभ के सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता, संवेदनशीलता और मानव सेवा को दें सर्वोच्च प्राथमिकता: राष्ट्रपति

'गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी और संपन्न आबादी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए'

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि युवा डॉक्टर पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और चिकित्सा सेवाओं में करुणा, संवेदनशीलता तथा मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान दें। विज्ञान भवन में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने चिकित्सा शिक्षा में छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना



की। उन्होंने कहा कि बेटियों की उपलब्धियां चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी और संपन्न आबादी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रपति ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अस्पताल की ओपीडी में 19 लाख से अधिक मरीज पहुंचे। इससे यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और क्लीनिकल ज्ञान हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला मुर्मु ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया है। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक का विस्तार हुआ है। देशभर में करीब 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी चिकित्सा शिक्षा और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अपने घरों के नजदीक बेहतर इलाज मिलना संभव हुआ है। उन्होंने टेलीमेडिसिन को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से भौगोलिक दूरियों को कम कर दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श पहुंचाया जा सकता है।

'फिक्की के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मानी आर्थिक चुनौतियां'

सरकार अपनी विफलता स्वीकार करे: जयराम रमेश

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को फिक्की (एफआईसीसीआई) कार्यक्रम में मौजूद बड़े उद्योगपतियों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोजगार और वेतन से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करेंगे और वही बातें दोहराएंगे जो कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरा सच नहीं बताया। पीएम मोदी ने गुरुवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग जगत से सवाल किया कि क्या सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और अन्य आर्थिक सुधारों (जिनका मकसद उद्योगों को बढ़ावा देना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आसान बनाना था) के बाद उन्होंने वास्तव में अधिक रोजगार पैदा किए हैं और कर्मचारियों की आय बढ़ाई है? जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 12 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों को सलाह दी है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री ने ठीक वही बातें दोहराईं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है। असल में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी चिंताओं को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। ' उन्होंने पीएम मोदी द्वारा उठाई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा, 'वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। टैक्स की दरों में कटौती की गई है ।

सोनिया गांधी की पुस्तक में वीर सावरकर पर टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव' में वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक और भ्रामक टिप्पणियों को लेकर शिवसेना नेता विष्णु गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सोनिया गांधी और पुस्तक के प्रकाशकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने मीडिया को जारी बयान में आरोप लगाया कि पुस्तक के पृष्ठ संख्या 201 और 443 पर वीर सावरकर के ऐतिहासिक बलिदान पर सवाल उठाए गए हैं और उनके बारे में तथ्यहीन बातें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि काला पानी की अमानवीय यातनाएं सहने वाले महान क्रांतिकारी वीर सावरकर



का अपमान देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे सदैव वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। ऐसे में पुस्तक में की गई टिप्पणियों से बालासाहेब ठाकरे के अनुयायियों, मराठी अस्मिता और करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिवसेना नेता ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पुस्तक पर देशभर में तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

अपने देश के झंडे वाले जहाजों पर हमले से नाराज भारत, कहा- नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। होर्मुज स्ट्रेट में हाल में हुए हमलों को लेकर भारत ने अपनी चिंता दोहराई है। भारत सरकार ने कहा कि वह वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करती है। नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एमईए प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि इन हमलों में भारतीय नाविकों की जान गई है और कुछ घायल भी हुए हैं। कुछ हमले भारतीय झंडे वाले जहाजों पर भी हुए हैं। भारत ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने बताया कि भारत का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल की जानी चाहिए।



भारत ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है।

हाल ही में हुए एक अन्य हमले पर भी भारत ने बयान जारी किया था और इस मामले में कई पक्षों के संपर्क में है।

सरकार ने कहा कि समुद्री समुदाय की सुरक्षा और भलाई भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कर्मी (सीफेयरर) समुदायों में से एक है और उसकी संख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मानी जाती है। बुधवार को ही बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट के पास मालवाहक जहाज 'अल-फतेह' के डूबने के बाद दो भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। बुधवार को ही लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर 'एमटी नेविग-8 मेसी' पर फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट के पास पहुंचते समय एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। गनीमत रही कि जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों समेत पूरा चालक दल सुरक्षित है। घटना के बाद भारतीय अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला 18 नवंबर को हुआ। उन्होंने बताया कि जहाज पर मौजूद तीनों भारतीय नागरिक और अन्य सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, एक भारतीय अधिकारी को प्राथमिक उपचार और चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया।

दिव्यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर भारत ने प्रतिबद्धता दोहराई

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हैग्रास के साथ चर्चा की। इस दौरान, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल सुलभता और समावेशन को बढ़ावा देने की भारत की कोशिशों पर प्रकाश डाला गया। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने डिजिटल समावेशन का समर्थन करने वाली कई पहलों को पेश किया। इनमें 'भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) 3.0' शामिल हैं, जो 'वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्ल्यूसीएजी) 2.1 लेवल एए' के अनुरूप हैं। इसके अलावा, आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की सुलभता के लिए 'भारतीय मानक आईएस 17802' भी शामिल है, जिसे 2023 में संशोधित आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत लागू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुलभता प्रमाणन और एसटीक्यूसी के माध्यम से वेबसाइटों व ऐप्स की टेस्टिंग के बारे में भी बताया। इसके तहत 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया गया है। साथ ही, 'सुगम्य वेब' और 'सत्या' जैसे डिजिटल टेस्टिंग टूल्स के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में यूएक्स4जी का भी जिक्र किया गया, जिसने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को यूएक?स ऑडिट और डिजाइन सपोर्ट दिया है। इसके 'रेडी-टू-यूज' एक्सेसिबिलिटी विजेट का इस्तेमाल 1,800 से अधिक वेबसाइटें कर रही हैं। 'भाषिणी', 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं देने वाला 'उमंग' प्लेटफॉर्म, और बहुभाषी व वॉयस-आधारित सुविधाओं वाला 'नमस्ते भारत एआई' नागरिक गाइड शामिल हैं।

संक्षिप्त डायरी

आकर्षक नंबरों की नीलामी के नतीजे जारी

अनप्लग इंडिया

नोएडा। निजी वाहनों की सीरीज यूपी16 जीबी के आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की नीलामी के नतीजे गुरुवार को जारी हो गए। वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नीलामी के नतीजे देख सकते हैं। परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नतीजों के मुताबिक नीलामी में 27 नंबर बिके हैं। इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ समेत अन्य नंबर शामिल हैं। नीलामी के बाद बचे नंबरों के लिए शुक्रवार से फिर से पंजीकरण शुरू होंगे। चार दिन पंजीकरण की प्रक्रिया चलेगी और उसके अगले तीन दिन तक नंबरों की बोली लगेगी। तीसरे दिन शाम छह बजे परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नीलामी के नतीजे जारी हो जाएंगे इसके बाद बचे नंबर पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर बुक होंगे। जो व्यक्ति पहले बुकिंग कर लेगा, उसके वाहन के लिए नंबर को आवंटित कर दिया जाएगा।

फेफड़े की गंभीर बीमारी के लिए क्लीनिक शुरू

अनप्लग इंडिया

नोएडा। सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल ने फेफड़े की गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए लंग फेलियर क्लीनिक की शुरूआत गुरुवार को की। क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुला रहेगा। क्लीनिक में पल्मोनॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉ. राहुल शर्मा और वरिष्ठ डॉ. गोविनी बालासुब्रमणि की देखरेख में मरीजों का इलाज किया जाएगा। मरीजों की देखरेख में काम करेंगे।

राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगी जिले की मोनिका

अनप्लग इंडिया

नोएडा। जिले महिला एथलीट मोनिका 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंच चुकी हैं। प्रतियोगिता में एथलीट 400 मीटर बाधा दौड़ में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की ओर से मध्यप्रदेश के भोपाल में 21 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनके बीच 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने के लिए एथलीट मोनिका गुरुवार को भोपाल पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार को पंजीकरण के बाद 21 नवंबर से अपनी रफ्तार का प्रदर्शन करेंगी। दादरी क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी मोनिका दुजाना गांव स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं और प्रशिक्षक सुनील कुमार नागर की निगरानी में एथलेटिक्स के गुर सीखती हैं। खिलाड़ी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमीक्रॉन-3 स्थित द एथलेटिक्स फ्यूचर अकादमी में भी कोच सोनू कुमार, मुन्नी नागर से प्रशिक्षण लेती हैं। प्रशिक्षक सुनील नागर ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए एथलीट मोनिका का चयन प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित 70वीं प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ है। 100 मीटर बाधा दौड़ में भी उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था।

2200 से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहन कबाड़ केंद्रों में पहुंचे

अनप्लग इंडिया

नोएडा। जिले में पंजीकृत 2200 से अधिक वाहन परिवर्तन योजना के तहत कबाड़ केंद्रों में पहुंचे हैं। यहां पर दो अधिकृत वाहन कबाड़ केंद्र हैं, जहां पर इन गाड़ियों को कटवाया गया है। एआरटीओ नंदकुमार ने कहा कि मुख्यालय की ओर से 9400 से अधिक पुराने व्यवसायिक वाहनों को कबाड़ में कटवाने और गाड़ी मालिक को परिवर्तन योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के बारे में वाहन मालिकों को जागरुक किया जा रहा है। यहीं वजह है कि लक्ष्य के मुकाबले 20 फीसदी से अधिक वाहनों को उनके मालिकों ने कबाड़ केंद्रों में कटवा दिया है। परिवर्तन योजना बीएस-4 या उससे पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना है। इसे 3 जून 2026 को मंजूरी मिली और 14 जुलाई 2026 को शुरू किया गया। इसके जरिए योजना में पंजीकृत होने वाले वाहन मालिकों को कई तरह की आर्थिक राहत दी जा रही है।

कोर कमेटी की बैठक में उठा शहर की खराब सड़कों और सफाई का मुद्दा

अनप्लग इंडिया

नोएडा। भाजपा कोर कमेटी की बैठक प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा में स्थित पुलिस कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जिले की खराब सड़कों का रहा और सफाई का रहा। जिसे शीघ्र दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों और सफाई की समस्या पर चर्चा बैठक में शामिल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सड़को की खराब हालत और नोएडा में सही से साफ-सफाई न होने का मामला उठाया गया और इसको लेकर नाराजगी जतायी गई। जिस पर निर्देश दिए गये कि अगले कुछ दिनों में ही सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और सड़कों को सही कराया जाए। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के फोन न उठाने और पार्टी के संगठन के लोगों की बात न सुनने की शिकायत भी की गई। इसके अलावा धारा-10 के मामले को भी बैठक में उठाया गया। पार्टी के नेताओं ने अन्य मामले भी उठाये। जिन्हें अधिकारियों के समक्ष रखते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारियों के द्धारा पार्टी के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों को पर्याप्त सम्मान देकर उनकी बात सुनी जाए और क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कर पूरे जिले में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मंडल अध्यक्षों की शिकायतों पर निर्देश प्रभारी मंत्री ने एक दिन पूर्व पार्टी के कार्यकताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याएं जानी थी। पार्टी के नेताओं के अनुसार इस बैठक में मंडल अध्यक्षों ने कहा था कि सरकारी कार्यालयों में उनकी बात नहीं सुनी जाती। जिसको लेकर कोर कमेटी की बैठक में नाराजगी जतायी गई और निर्देश दिए गये कि मंडल अध्यक्षों को सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त सम्मान देकर अधिकारी उनकी शिकायतों को सुनें। अधिकारी की टिप्पणी पर जताई नाराजगी बैठक के दौरान जिले के एक प्राधिकरण के अधिकारी द्धारा स्वंय को एक संगठन से जुड़ा बताया जाने लगा। जिसकी इस टिप्पणी को लेकर बैठक में अचानक से माहौल गरमा गया और अधिकारी की उक्त टिप्पणी को लेकर प्रभारी मंत्री और अन्य लोगों ने भी नाराजगी जतायी।

पॉश सोसाइटी के फ्लैट में करोड़ों की चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

नोएडा। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने सेक्टर-50 स्थित एक सोसाइटी के दो फ्लैट से करीब दो करोड़ की चोरी करने वाले तीन बदमाशों को बुधवार देर रात मेघदूतम पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते में पांच लाख रुपये भी फ्रीज कराए। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-50 स्थित द क्रिसेंट अपार्टमेंट के एक फ्लैट में नितिन जैन रहते हैं। उनके ऊपर वाले फ्लैट में धनलक्ष्मी रहते हैं। दोनों के फ्लैट में 12 अक्तूबर को चोरी हुई थी। घटना के समय दोनों परिवार घर से बाहर गए थे। नितिन जैन ने गहनों और नकदी समेत करीब दो करोड़ रुपये का सामान चोरी होने का दावा किया था। पुलिस ने कसे दर्ज कर चोरों को पकड़ने के लिए चार टीम गठित की थीं। गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस ने बुधवार देर रात सेक्टर-50 स्थित मेघदूतम पार्क के पास से तीन आरोपियों को दबोच लिया।

ग्रेनो में वायु प्रदूषण से निपटने को प्राधिकरण ने तेज की मुहिम

अनप्लग इंडिया



नोएडा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण ने कवायद तेज कर दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही प्रदूषण के लिहाज से चिह्नित सभी हॉट-स्पॉट पर रोकथाम के प्रभावी उपाय किए जाएंगे। वर्तमान में शहर में पांच से अधिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। ग्रेटर नोएडा के सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने शुक्रवार को सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीईओ ने प्रदूषण रोकने के लिए सभी उपाय करने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुमार्ना और जागरूकता के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने ने कहा कि सड़कों के किनारे जहां भी कच्चा मार्ग है, वहां घास लगाएं, ताकि धूल न उड़े। मशीनों से सड़कों की सफाई दो शिफ्ट में कराएं। दिन और रात में सड़कों की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदूषण के लिहाज से चिह्नित सभी हॉट-स्पॉट पर रोकथाम के उपाय करें। एसीईओ के साथ ही महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें। सीईओ ने जरूरत के हिसाब से एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में निर्धारित सभी कूड़ा संकलन केंद्रों से नियमित कूड़ा उठवाने और साइटों पर निर्माण सामग्री ढककर रखने को कहा है। डॉ. बलकार सिंह ने कहा कि प्रदूषण से संबंधित नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रेटर नोएडा की आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के ऑफिस, सामुदायिक केंद्रों आदि के नोटिस बोर्ड पर पंफलेट चस्पा करें। बल्क वेस्ट जेनरेटरों, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एनजीओ के जरिए जागरूकता अभियान चलाएं। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा में ई-चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और सर्दियों में लकड़ी के अलाव की जगह इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। सीईओ ने हॉर्टिकल्चर वेस्ट को जलाने के बजाय वर्मी कंपोस्ट बनाने पर जोर दिया। हॉर्टिकल्चर या अन्य वेस्ट में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम के निर्देश का पालन सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि हर समय करना जरूरी है। सीईओ ने साफ कहा कि प्रदूषण रोकने के नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुमार्ना लगाकर कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, एसीईओ नूपुर गोयल, महाप्रबंधक एके सिंह, उप महाप्रबंधक विजय रावल सहित सभी वरिष्ठ प्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर रिसेल करने का झांसा देकर 20.36 लाख रुपये ठगे

अनप्लग इंडिया

नोएडा। साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर 20.36 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने ईकॉमर्स प्लेटफार्म पर रिसेल से होने वाले प्रॉफिट का स्कीम चार्ट भेजा तथा इसी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन रि-सेल अकाउंट खोलने का लालच दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के निराला एस्टेट सोसाइटी निवासी तथागत अंकित ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से बिहार के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। नायरा देसाई नामक एक महिला ने 13 नवंबर को टेलीग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क किया। उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर रिसेल से होने वाले फायदे के बारे में उनसे बातचीत की। उसने कहा कि इसी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन रिसेल अकाउंट खोलने से उनका फायदा होगा। उसने कहा कि हम दोनों साथ मिलकर निवेश करते हैं। निवेश के नाम पर ठगी पीड़ित के अनुसार उसने महिला की बात पर विश्वास किया तथा धीरे-धीरे निवेश करना शुरू कर दिया। शुरूआती दौर में उन्हें ऑनलाइन प्लेटफार्म पर रिसेल करने से काफी मुनाफा हुआ। उन्हें महिला की बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने धीरे-धीरे करके 10 बार में 20 लाख 36 हजार रुपये ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी में निवेश कर दिए। जब उन्होंने अपनी रकम निकालनी चाही तो आरोपियों ने और रकम की मांग की। उसके बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उन्हें जमा रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निजी अस्पताल के डॉक्टर भी नशामुक्ति अभियान से जुड़ेंगे

अनप्लग इंडिया

नोएडा। निजी अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी राष्ट्रीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान से जुड़ेंगे। 80 निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और प्रतिनिधियों को अभियान के तहत प्रशिक्षित किया गया है। निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की नशे की लत होने काउंसलिंग और जागरूक करना होगा। ताकि वे नशा छोड़ सके। निजी अस्पतालों में मरीजों की काउंसलिंग राष्ट्रीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत ओपीडी, आईपीडी में आने वाले मरीजों की बीमारी के साथ ही नशे की लत की भी जानकारी लेंगे। नशे की जानकारी मिलने पर मरीज उनकी काउंसलिंग भी करनी होगी। साथ ही नशे से होने वाली हानि और इसे छोड़ने के फायदे बताने होंगे। बीमारी के साथ नशा करने से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी मरीजों को जानकारी दी जाएगी। नशा मुक्ति को लेकर अगले 60 दिनों में हुए जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग, सहित अन्य कार्यों के बारे में अस्पतालों को बताना होगा। इसके वीडियो और फोटो भी स्वास्थ्य विभाग को देने होंगे। जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ. श्वेता खुराना ने बताया कि अस्पतालों के डॉक्टर या प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हुए हैं। वे अपने अस्पतालों में जाकर इसका विस्तार करेंगे। अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देंगे। ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। अगर अस्पतालों को नशा मुक्ति काउंसलर से संबंधित प्रशिक्षण की जरूरत है तो उसे हम पूरा करेंगे। अगर कोई बीमार व्यक्ति नशे की लत में है तो वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे में इस अभियान से मरीजों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। अगले दो महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखने की उम्मीद है। नशा छोड़ने की प्रक्रिया में लोग जिले में ढाई हजार से अधिक लोग नशा छोड़ने की प्रक्रिया में हैं। अक्तूबर में 296 लोगों ने नशा छोड़ने के लिए पंजीकरण कराया है। इनकी काउंसलिंग की जा रही है। जिले में छह स्थानों पर नशे की लत को खत्म करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं। इसके लिए तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने निजी अस्पतालों से भी समझौता साइन किया है, जिसके तहत डॉक्टरों और काउंसलरों की अलग-अलग ट्रेनिंग दी गई है। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी एक केंद्र चल रहा है।

छात्रा को दुष्कर्म और मारपीट के बाद जंगल में फेंका

अनप्लग इंडिया



ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर भाग गए। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता अपने मामा के यहां रहती है। वह कक्षा पांच में पढ़ती है। उसकी नानी और घर के सदस्य बुधवार रात पड़ोस में शादी के दौरान संगीत कार्यक्रम में गए थे। वह अपनी नानी का मोबाइल देने के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी पड़ोसी ने छात्रा को दुकान पर चलने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। आरोपी छात्रा को जंगल की तरफ ले गया। खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर बेल्ट से बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे जंगल में लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। देर रात तक छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।मोबाइल की लोकेशन से छात्रा तक पहुंची पुलिस : परिजनों की शिकायत पर बादलपुर कोतवाली पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला की छात्रा के पास उसकी नानी का मोबाइल है। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और छात्रा का पता लगाया। पुलिस और परिजन छात्रा की तलाश में जंगल में पहुंचे। छात्रा वहां एक खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। कासना के जिम्स अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। शरीर पर चोट के निशान हैं। गले पर भी निशान मिले हैं। अंदरुनी चोट भी लगी हैं। परिजनों और पुलिस के अलग-अलग दावे परिजनों का आरोप है कि घटना में तीन लोग शामिल हैं। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उसे बेरहमी से पीटा गया है। वहीं, पुलिस एक आरोपी होने का दावा कर रही है। परिजनों का आरोप है कि घटना में तीन लोग शामिल रहे। छात्रा ने परिजनों को इस बारे में बताया है। आरोप है कि छात्रा के साथ हैवानियत की गई। छात्रा की हालत गंभीर है। आरोपी की गिरफ्तारी और घटना का समय डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया रोहित उर्फ चंदा पहले से ही छात्रा का परिचित है। आरोपी छात्रा के मामा का दोस्त है। वह मामा का पड़ोसी है। छात्रा उसे मामा कहकर बुलाती थी। छात्रा अपनी मर्जी से बाइक पर बैठकर गई थी। इस घटना में आरोपी अकेला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चार घंटे तक खेत में तड़पती रही छात्रा परिजनों ने बताया कि आरोपी ने करीब 9:30 बजे छात्रा को बाइक से अगवा किया। इसके बाद उसे जंगल में ले गया। उसके साथ हैवानियत की और जंगल में छोड़कर भाग गया। करीब चार घंटे तक छात्रा खेत में पड़ी रही। परिजन पुलिस की मदद से करीब 1:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में पड़ी मिली छात्रा को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद से छात्रा के परिवार के लोगों में आक्रोश है। पहले की घटनाएं ग्रेनो वेस्ट के हल्दौनी गांव में तीन महीने पहले छह साल की मासूम बच्ची से बलराज ने दरिंदगी की थी। इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में ढेर किया था। बलराज बच्ची के शव को बोर में भरकर घर से दो किलोमीटर दूर खेत में जाकर फेंक आया था। बच्ची के शव को बोरे में ले जाते वक्त वह सीसीटीवी में कैद हुआ था। पहले भी ऐसे मामले सामने आए- दादरी कोतवाली क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव के पास एक सोसाइटी में रहने वाली चार साल की बच्ची को 12 अगस्त को पड़ोसी ने गलत तरीके से छुआ। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

बूथ स्तर पर वोट रक्षक अभियान तेज करेगी कांग्रेस

अनप्लग इंडिया

नोएडा। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को बिसरख स्थित जिला कांग्रेस मुख्यालय में हुई। बैठक में 26 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही जिले में चलाए जा रहे 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी एवं पूर्व विधायक संजीव आर्या ने संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों तथा बूथ स्तर पर चल रहे वोट रक्षक अभियान की प्रगति की समीक्षा की। संजीव आर्या ने कहा कि कांग्रेस का वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संवैधानिक मूल्यों तथा प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा का जनअभियान है। उन्होंने मंडल अध्यक्षों से बूथवार वोट रक्षकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण तथा मतदाता सूचियों से हटाए गए नामों के भौतिक सत्यापन की जानकारी ली। वहीं नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव ओमवीर यादव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत देश का आम मतदाता है। संविधान ने प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार दिया है। इस अधिकार की रक्षा करना लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में केवल औपचारिक रिपोर्टिंग पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि वास्तविक जमीनी कार्य, तथ्यात्मक जानकारी और नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि प्रत्येक मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक प्रशिक्षित वोट रक्षक नियुक्त हो। वोट रक्षक संबंधित बूथ की मतदाता सूची से हटाए गए नामों का जमीनी सत्यापन करें तथा प्राप्त तथ्यों को निर्धारित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संगठन के केंद्रीय कंट्रोल रूम तक पहुंचाएं। बैठक में मुकेश यादव, अजय चौधरी, अशोक पंडित,

ग्रेनो की अंसल गोल्फ लिंक-वन सोसाइटी में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी

अनप्लग इंडिया



नोएडा। शहर की अंसल गोल्फ लिंक-वन सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके रखरखाव कार्य के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो एक साल तक जिम्मेदारी संभालेगी। आंतरिक सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण ने निविदा जारी की है। परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक सोसाइटी के ब्लॉक ए एवं सी में आंतरिक सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। इस पर 3.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से रखरखाव का कार्य न होने से सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। गड्ढे होने से लोगों को परेशानी होती है। दरअसल परी चौक के समीप सेक्टर ओमेगा-1 में अंसल गोल्फ लिंक-1 सोसाइटी 102 एकड़ में बसाई गई है। बिल्डर प्रबंधन के गायब हो जाने पर सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। रखरखाव का कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्री होल्ड सोसाइटी होने की वजह से प्राधिकरण विकास कार्य नहीं करा सकता है। पूर्व में हुए समझौते के तहत फ्री होल्ड सोसाइटी में आवंटियों द्वारा रुपया जमा करने पर ही प्राधिकरण द्वारा जरूरी विकास कार्य कराया जाएगा। इस समय पेयजल आपूर्ति, सीवर आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने का कार्य चल रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि सोसाइटी के ब्लॉक ए और सी की आंतरिक सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी निविदा जारी की गई है। सोसाइटी में रखरखाव कार्य के लिए भी एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

यौन शोषण मामले में प्रेमी के खिलाफ मुकदमा

अनप्लग इंडिया



नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी में रहने वाली युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी वैभव अस्थाना और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात जीवनसाथी ऐप के माध्यम से वैभव अस्थाना से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और करीब एक साल तक रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान वैभव ने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी कराई। आरोप है कि वैभव के पिता ने दूसरी जाति होने के कारण शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद वह गांव चला गया, लेकिन बीच-बीच में युवती से मिलने आता रहा। आरोप है कि वर्ष 2025 में वैभव अचानक उससे संपर्क तोड़कर गायब हो गया। इस बीच युवती की दूसरी जगह शादी तय हो गई और सगाई भी हो गई। करीब एक साल बाद वैभव ने दूसरे नंबर से संपर्क किया और शादी का भरोसा देकर दोबारा संबंध बनाने शुरू कर दिए। युवती ने उसके भरोसे पर अपनी तय शादी भी तोड़ दी। आरोप है कि वैभव ने उसे अपने घर बुलाया, साथ रखा और मांग में सिंदूर भरकर पत्नी की तरह रहने का भरोसा दिया। युवती के मुताबिक, दीवाली के बाद जब उसने शादी की बात की तो वैभव ने उसे अपमानित किया। युवती का आरोप है कि वैभव ने उसके चरित्र और परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणियां की और शादी करने से इनकार कर दिया। अब 13 नवंबर से उसे फोन कर धमकियां दी जा रही हैं। आरोपी उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस से शिकायत की है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

राहुल-सोनिया के सामने परेशान भाजपा

बच्चों और युवाओं को आडंबर कभी पसंद नहीं आए। पिछले जमाने में भी नयी पीढ़ी आडंबरों के खिलाफ ही थी, लेकिन तब समाज की मर्यादाएं, रिवाज अलग थे और सोशल मीडिया भी नहीं था। इसलिए आडंबरों की ऐसी धज्जियां नहीं उड़ाई गई, जैसी अब उड़ाई जा रही हैं। सैकड़ों मीम्स और रील्स ढकोसलों का मखौल उड़ाते हुए रोजाना बनाए जाते हैं। उसी से जेन जी की नब्ज टटोली जा सकती है।



राहुल गांधी ने 13 अगस्त को रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वे इन लोगों को पागल कर देंगे। उस समय तो वोट चोरी और जेन जी आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस के अत्याचार के संदर्भ में राहुल ने यह बात कही थी, क्योंकि तब राहुल के सवालों के जवाब मोदी और शाह नहीं दे पा रहे थे, उल्टा राहुल से बचे-बचे फिर रहे थे। ये दोनों मुद्दे तो अब भी हैं, लेकिन अब इनके साथ कुछ और मुद्दे जुड़ चुके हैं, जिन पर मोदी, शाह या भाजपा की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि वाकई इनका दिमाग भन्नाया हुआ है कि हम राहुल गांधी को किस तरह कमजोर करें, कैसे उन्हें दबाव में लाएं। ऊपर से अब सोनिया गांधी की चुनौती भी खड़ी हो गई है। 2024 में जब सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था, तो यह भाजपा के लिए बड़ी राहत का विषय था। क्योंकि उनकी लोकसभा में मौजूदगी भाजपा को वैसे ही परेशान करती है, जैसे अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की करती है। बल्कि लोकसभा क्या, इन तीनों की सक्रिय राजनीति में मौजूदगी से ही भाजपा को तकलीफ है। गौर कीजिए कितना लंबा अरसा बीत गया लेकिन भाजपा अब तक इनके खिलाफ वंशवाद के वार को रोक नहीं पाई है। हर हमले में पहला हथियार वंशवाद का ही निकलता है। ये और बात है कि अब भाजपा की वंशवादी बेल भी उतनी लंबी हो चुकी है कि उसकी ये कुंठा खत्म हो सके। भाजपा के पास दूसरा हथियार चरित्र हनन का है। सोनिया गांधी को विदेशी मूल का होने के कारण ही अपमानित नहीं किया गया, कभी जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, बार डांसर और न जाने कितने लांछन लगाए गए। लेकिन भाजपा की तकलीफ फिर भी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि सोनिया गांधी की गरिमा और नैतिक बल के सामने ये सारे लांछन भाजपा नेताओं के मुख की गंदगी ही बढ़ा गए। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। युवराज, शहजादा, पप्पू, फेल प्रोडक्ट तमाम शब्दों के जरिए उन्हें नाकाम राजनेता बताने की कोशिश हुई। मगर अब वही राहुल गांधी मोदी-शाह के सामने नेता प्रतिपक्ष बनकर ही नहीं बैठे, पूरे देश में अपने पद की जिम्मेदारी निभाते हुए जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए, वह राहुल गांधी करते हैं। लिहाजा भाजपा का चरित्र हनन वाला हथियार भी बेकार हो गया। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की दोहरी चुनौती भाजपा के सामने आ गई है। मोदी को वैसे भी डबल शब्द से प्यार है। इसलिए जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए, उसे डबल इंजन सरकार कहते हैं। तो अब डबल ट्रबल यानी दोहरी परेशानी उनके सामने आ गई है,

जब संविधान की रक्षा 'अगली सुनवाई' पर टल जाए, तो लोकतंत्र कौन बचाएगा?

-सचिन कुमार गौतम

देश में लोकतंत्र को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को चुनौती देने की आशंकाओं के बीच लोग बार-बार न्यायपालिका की ओर देखते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय देगा, जिनसे आम नागरिक को विश्वास बना रहे कि भारत का विचार–उदार, लोकतांत्रिक, समावेशी और विविधता में एकता पर आधारित–हर हाल में सुरक्षित रहेगा। यही विचार स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत था और संविधान की आत्मा भी है।

आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला इसी विश्वास से बंधा रहा कि भारत एक ऐसा देश बनेगा, जहां हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। संविधान निर्माताओं ने इसी भावना को संस्थागत रूप दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया, क्योंकि इसने जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर नागरिक को राजनीतिक समानता का अधिकार दिया।

लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस विश्वास को झकझोरा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ट्रक्र), बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत, और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के मुख्य न्यायाधीश के प्रति असंवेदनशील व्यवहार–इन तीनों प्रकरणों ने एक ही सवाल उठाया है: क्या न्यायपालिका नागरिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और जनविश्वास की रक्षा कर पाएगी?

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्ट्रक्र को लेकर विवाद तेज हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं या हटाए गए हैं, जिससे आम नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची को सटीक और भ्रष्टाचार-मुक्त रखना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी वैध मतदाता को अनायास वंचित न किया जाए।

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि स्ट्रक्र से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता नहीं थी और चुनाव आयोग के अंदरूनी निर्णय-प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से 48 औपचारिक सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। ये सवाल स्ट्रक्र शुरू करने का निर्णय किसने और कैसे लिया, क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, फॉर्म-6 में बदलाव कैसे हुआ, और चुनाव आयुक्तों ने कब आपत्ति या असहमति दर्ज की–जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हैं।

यह विवाद केवल तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं है। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। यदि नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुनवाई और सुधार का अवसर नहीं है, तो नागरिक का भरोसा चुनाव प्रणाली से कमजोर होगा। इसलिए अदालत का यह तय करना जरूरी है कि चुनाव आयोग से जवाब मांगे जा सकते हैं या नहीं।

सोमवार को दायर आवेदन पर कपिल सिब्बल ने अदालत से चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की आपत्तियां सुनने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। यह निर्णय तकनीकी रूप से प्रक्रियागत लग सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक और संवैधानिक महत्व बड़ा है। यदि अदालत विपक्ष को 48 सवाल पूछने की अनुमति देती है, तो चुनाव आयोग को अपने निर्णयों की प्रक्रिया, सहमति, दस्तावेज और जवाबदेही सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी पड़ सकती है।

दूसरा प्रकरण बिलकिस बानो के

आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला इसी विश्वास से बंधा रहा कि भारत एक ऐसा देश बनेगा, जहां हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। संविधान निर्माताओं ने इसी भावना को संस्थागत रूप दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया, क्योंकि इसने जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर नागरिक को राजनीतिक समानता का अधिकार दिया। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस विश्वास को झकझोरा है।

मामले से जुड़ा है, जो 2002 के गुजरात दंगों की सबसे पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या की गई थी। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय और न्यायिक विश्वास का प्रश्न भी है।

28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने इसका आधार यह रखा कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून दोनों से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए सजा निलंबित कर जमानत दी गई। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी।

यह फैसला कानूनी रूप से संभव हो सकता है, लेकिन इसके सामाजिक और नैतिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलकिस बानो ने अपने अजन्मे बच्चे को खोया, अपने परिवार के सदस्यों की हत्या देखी और सामूहिक बलात्कार की असहनीय पीड़ा सही। उनके लिए न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन और गरिमा की बहाली का सवाल है।

इससे पहले भी दोषियों को 2002 में समय से पहले रिहा किया गया था। उस फैसले को चुनौती दी गई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस निर्णय को रद्द किया था। अब फिर दो दोषियों को जमानत मिलने से बिलकिस बानो के सामने वही डर लौट आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि जिस न्याय के लिए उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वह फिर छिन रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि जमानत देने से पहले उन्हें सुनने का मौका क्यों नहीं दिया गया।

अदालत के फैसले की आलोचना करना और कानूनी प्रक्रिया को समझना दो अलग बातें हैं। जमानत और सजा निलंबन अपराध की गंभीरता को खत्म नहीं करते, लेकिन जब पीड़िता को सुनवाई का अवसर नहीं मिला हो, तो न्याय की अनुभूति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया केवल तकनीकी रूप से सही न हो, बल्कि न्याय की भावना को भी पूरा करे।

तीसरा प्रकरण 16 नवंबर का है, जब वकील प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर सीधे सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि उनका मामला 2 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत के कार्यालय में दिया गया था, लेकिन 15 दिन बाद भी जवाब नहीं मिला। जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर विचार किया जाएगा, तो वकील ने कहा कि वे इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं और उनमें ईमानदारी नहीं है।

ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से अदालत की गरिमा के खिलाफ है और अवमानना की कार्रवाई का विषय बन सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी सोचना जरूरी है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। जब नागरिक या वकील को लगता है कि उनकी सुनवाई या जवाब में देरी हो रही है, तो उनका आक्रोश न्यायिक तंत्र के प्रति बढ़ती निराशा का संकेत हो सकता है।

न्यायपालिका की ताकत केवल अधिकार या आदेश से नहीं, बल्कि जनविश्वास से आती है। जब एक पीड़िता को डर लगे कि न्याय फिर छिन जाएगा, जब मतदाता को लगे कि उसका नाम सूची से हट सकता है, और जब अदालत के भीतर ही संवाद की गरिमा टूटे, तो यह केवल कुछ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं रहतीं। ये संकेत बन जाते हैं कि संस्थागत विश्वास कमजोर हो रहा है।

9 दिसंबर की सुनवाई में यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्र से जुड़े 48 सवालों पर क्या रुख अपनाती है। यदि अदालत चुनाव आयोग से स्पष्ट, शपथपूर्वक और दस्तावेजों के आधार पर जवाब मांगती है, तो यह मतदाता अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

बिलकिस बानो के मामले में भी अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता की सुनवाई, सुरक्षा और न्याय का अधिकार सुरक्षित रहे। और अदालत के भीतर के व्यवहार में भी संयम, संवेदनशीलता और गरिमा बनी रहनी चाहिए।

भारत का विचार केवल संविधान की किताब में नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकार, हर मतदाता के वोट और हर पीड़ित के न्याय की उम्मीद में जिंदा रहता है। न्यायपालिका को यह उम्मीद बनाए रखनी होगी।

वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी!

राजेन्द्र शर्मा

इस बढ़ते तूफान के सामने एक ओर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, बढ़ती आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे-साधे, पर्दे के पीछे से अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए उसने नये मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 से जोड़ी गयी अवैध घोषणा से पीछा छुड़ाने से लेकर, ईसीआइनैट के जरिए मतदाता सूचियों का नियंत्रण पूरी तरह से सीमा खन्ना के हाथों में सौंपने की स्थिति को पलटने तक के कदम उठाए हैं।

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन एक नया रूप ले रहा है। अक्टूबर में यह आंदोलन मुख्यतः देश की राजधानी में और उसमें भी विशेष रूप से जंतर-मंतर पर केंद्रित था और 1 नवंबर की रामलीला मैदान की विशाल रैली में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके बाद से लगातार इस आंदोलन का देश भर में फैलाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी तेरह विपक्षी पार्टियों की संयुक्त याचिका के अगले कदम के रूप में, चुनाव आयोग के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे पर, अदालत से तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आयोग से प्रश्न करने का अवसर मांगा है और इसके लिए अपने 48 प्रश्न रखे हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने, इस मामले में कोई भी निर्णय 9 दिसंबर तक के लिए खिसका दिया है, लेकिन आयोग को इस दौरान विपक्ष की उक्त प्रार्थना पर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दे दिया है। ऐसा लगता नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से आसानी से कोई राहत मिलेगी।

बहरहाल, इस बढ़ते तूफान के सामने एक ओर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, बढ़ती आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे-साधे, पर्दे के पीछे से अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए उसने नये मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 से जोड़ी गयी अवैध घोषणा से पीछा छुड़ाने से लेकर, ईसीआइनैट के जरिए मतदाता सूचियों का नियंत्रण पूरी तरह से सीमा खन्ना के हाथों में सौंपने की स्थिति को पलटने तक के कदम उठाए हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान छूट गए पहले के मतदाताओं को सूची में लाने के दोबारा प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जो इस अर्थ में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के ही औचित्य पर सवाल खड़ा कर देता है कि यह लगभग प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना है कि किसी न किसी तरह से, इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं। एसआईआर के प्रक्रिया के नाम पर, 2024 की मतदाता सूचियों में से अब तक 13 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संख्या इतनी बड़ी है कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग भी इसके 'सामान्य' होने का स्वांग नहीं कर सकता है। फिर भी, चुनाव आयोग जहां अदालती चुनौतियों के सामने, सब कुछ नियमानुसार होने के दिखावे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, वहीं एसआईआर को जारी रखकर और विधानसभाई चुनावों के अगले चरण के लिए अपनी तैयारियों की घोषणा कर, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होने का दिखावा कर रहा है।

और संघ परिवार तथा उनकी मोदीशाही, जो चुनाव आयोग को अपना वफादार बनाने के मुख्य



लाभार्थी हैं, 'वोट चोरी' के आरोपों से बचाव की कोशिश में, ध्यान बंटाने के अपने जाने-पहचाने खेल में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें खासी महारत हासिल भी है। इसी खेल के हिस्से के तौर पर, कांग्रेस और उसकी तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित, तीन दिनी इंडिया समिट में, विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर, भारत के हालात पर चर्चा कर के, 'भारत को बदनाम' किए जाने का झूठा शोर मचाया जा रहा है। इस तरह का तकाजा सरासर जनतंत्र-विरोधी बल्कि फासीवादी है। जनतंत्र, बराबरी और न्याय के तकाजे अपनी प्रकृति में अविभाज्य हैं और इसलिए सार्वभौम हैं और उनके सार्वभौम होने के साथ ही मानवता का विकास जुड़ा हुआ है और इन मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की एकजुटताओं को न देशों की सीमाओं में बांटा जा सकता है और न कभी वास्तव में बांटा जा सकता है। कम से कम भारत जैसे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लंबे दौर के जरिए विदेशी गुलामी से आजाद हुए देश के लिए स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय एकजुटताओं के महत्व को समझने-समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी इतिहास के हिस्से के तौर पर स्वतंत्रता के बाद भारत ने न सिर्फ अनेक दूसरे पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रेरित किया था बल्कि स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी यथासंभव मदद भी की थी।

आगे चलकर, इन्हीं मूल्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, नव-स्वाधीन तथा कम विकसित देशों की व्यापक एकजुटता तथा महत्वपूर्ण आवाज को रूप दिया था। लेकिन, नरेंद्र मोदी जिस संघ की परंपरा के वारिस हैं, वह चूंकि आजादी की लड़ाई के विरोध में ही खड़ा रहा था, इन सार्वभौम मूल्यों पर आधारित एकजुटताओं से उसका कोई परिचय ही नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि मोदी राज में भारत की विदेश नीति को इन सभी मूल्यों से बरी कर के महज 'लेन-देन' की नीति बनाकर छोड़ दिया गया है। हां! चूंकि इस लेन-देन में, अपने से ताकतवर की खुशामद करना भी शामिल है, इसलिए पूरा संघ परिवार इसका तो शोर मचा रहा है कि एक इतालवी नेता ने 'वोट छोड़ गद्दी छोड़' क्यों कह दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के 'अब की बार ट्रंप सरकार' का नारा लगाकर अमेरिका के चुनाव में भारतीयों के वोट ट्रंप की गोद में डालने की कोशिश करने में, कुछ भी गलत नहीं लगा।

इसी दौरान अमित शाह ने ही ध्यान बंटाने के ही एक और पैंतरे में, इसकी अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी कि मानसून सत्र को अब तक खत्म न कर के स्थगित ही किए जाने के सहारे, संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाकर, महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाने की आड़ में परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन दोबारा लाया जाएगा और इस बार उसे पारित करा लिया जाएगा। एनडीए के प्रकटतः संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत से काफी दूर होने के बावजूद, शाह ने प्रेस के सामने 10-15 फालतू वोट के साथ दोनों सदनों में संशोधन पारित कराने का दावा किया था।

फिर भी संघ-भाजपा का ध्यान बंटाने का यह खेल सिर्फ 'देश की बदनामी' का शोर मचाने या संसद का विशेष बुलाकर परिसीमन थोपने के दावों तक ही सीमित नहीं रहा है। ध्यान बंटाने का इससे भी बड़ा और खतरनाक खेल, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां अगले साल की पहली तिमाही में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। मथुरा में भाजपा के दो-दिवसीय क्षेत्रीय सांगठनिक सम्मेलन के मौके पर, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर 'भव्य मंदिर' का निर्माण 2027 के विधानसभाई चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस घोषणा की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी की जिस बैठक के मौके पर उक्त घोषणा की गयी, उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा तथा संघ के केंद्र व राज्य, दोनों के शीर्ष नेता मौजूद थे। यह दूसरी बात है कि चुनाव से पहले ध्यान बंटाने के इस खेल का एक मकसद और था। इसका संबंध, खुद सत्ताधारी पार्टी में असंतोष भड़कने की आशंकाओं की ओर से ध्यान बंटाने से था। ये आशंकाएं इसकी व्यापक रूप से आयी खबरों से भड़क रही थीं कि लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए 202 नामों की सूची दिल्ली में पार्टी केंद्र के पास भेजी गयी थी! चूंकि इसमें बड़ी संख्या में निवर्तमान विधायकों की छुट्टी का संकेत माना जा रहा था, इससे सत्ताधारी पार्टी में जबर्दस्त हड़कंप मच गया, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर, ऐसी कोई सूची बनने का खंडन कर दिया।

उधर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद ही एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने और मुसलमानों के वोट बढ़ने के अपने दावों से, न सिर्फ एसआईआर की विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दिया है बल्कि मौर्य के इशारे को ही और गाढ़ा करते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के अलावा सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन के भरोसे चुनाव लड़ेगी। विडंबना यह है कि आदित्यनाथ, मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव को इसका ताना मार रहे हैं कि वह एसआईआर को निरस्त ही किए जाने की मांग क्यों नहीं करते हैं! ध्यान बंटाने की इन कोशिशों से साफ है कि भाजपा, किस कदर घबरायी हुई है।

सिर्फ कागजों पर साकार नहीं होता स्वच्छ गांव का सपना

हिमानी थायत
बागेश्वर, उत्तराखंड

स्वच्छ गांव की तस्वीर केवल साफ-सुथरी गलियों और दीवारों पर लिखे स्वच्छता संदेशों से नहीं बनती। इसके लिए जरूरी है कि घर से निकलने वाला कचरा नियमित रूप से उठे, उसे रखने की जगह हो, गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था हो और उसे सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाए। जब गांव में यह व्यवस्था नहीं होती तो कचरा केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और आखिरकार नालियों, खेतों, रास्तों या जल स्रोतों के आसपास जमा होने लगता है।

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के मैगड़ी स्टेट गांव की कहानी इसी अधूरी व्यवस्था की ओर ध्यान खींचती है। पहाड़ों की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस गांव में कचरे की समस्या ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। बागेश्वर से करीब 42 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी लगभग 1566 है और यहां करीब 320 परिवार रहते हैं।

ग्रामीणों के अनुसार गांव में कूड़ा उठाने के लिए नियमित वाहन नहीं आता। नतीजा यह है कि लोग अपने स्तर पर कचरे को एक जगह इकट्ठा करते हैं, कई बार उसे जला देते हैं या नालियों और आसपास के खाली स्थानों में फेंक देते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। पानी के साथ बहता कचरा खेतों और छोटे नालों तक पहुंचता है, जिससे केवल गांव की सफाई ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि खेती, जलस्रोतों और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ता है।

इस संबंध में 45 वर्षीय खष्टी देवी भी पुष्टि करती हैं कि गांव में कूड़े की गाड़ी नहीं आती, इसलिए लोग कचरे को एक जगह जमा करके जला देते हैं। उनके अनुसार आसपास के इलाकों में भी लोग कचरे को नदी-नालों में फेंक देते हैं। वह कहती हैं कि जब कचरा संग्रहण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तो लोगों से केवल स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसके लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्था भी मौजूद हो।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण में भी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को ग्रामीण स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सरकार के अनुसार गांवों में कचरा संग्रहण, उसका अलगाव, परिवहन, कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायतों को कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। फिर सवाल यह है कि व्यवस्था होने के बावजूद मैगड़ी स्टेट जैसे गांवों में कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं



पहुंचती?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 तक देश के 5.19 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दर्ज की गई थी और 6.36 लाख से अधिक कचरा संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध बताए गए थे। यह निश्चित रूप से एक बड़ा विस्तार है, लेकिन ऐसे आंकड़ों की असली परीक्षा उन गांवों में होती है जहां व्यवस्था अभी भी ग्रामीणों के अनुभव का हिस्सा नहीं बन पाई है।

मैगड़ी स्टेट की समस्या केवल कूड़े की गाड़ी तक सीमित नहीं है। गांव में मौजूद एकमात्र कूड़ेदान भी सड़क से दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह दूरी और कठिन हो जाती है। 65 वर्षीय पन्ना देवी का कहना है कि गाँव में सड़क नहीं होने के कारण कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। यदि गांव के भीतर सड़क पहुंच जाए तो कचरे की गाड़ी घरों तक आ सकती है।

गांव में स्वच्छता का सबसे बड़ा भार अक्सर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो रोजमर्रा के घरेलू कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं। महिलाओं को घर का कचरा बाहर ले जाना, पानी और बच्चों की देखभाल के साथ घर के आसपास की सफाई बनाए रखना पड़ता है। जब कूड़ेदान दूर हो और कचरा संग्रहण की नियमित व्यवस्था न हो तो यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हीं के हिस्से आती है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए चढ़ाई चढ़कर कचरा ले जाना केवल असुविधा नहीं, बल्कि शारीरिक परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए ग्रामीण स्वच्छता की योजना बनाते समय यह देखना जरूरी है कि सुविधा वास्तव में गांव के हर व्यक्ति के लिए कितनी सुलभ है।

हालांकि इस गांव को स्वच्छ बनाने में यहां की किशोरियों और महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। नाममात्र संसाधन के बावजूद वह अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को व्यवस्था का साथ मिलना जरूरी है। स्वच्छता का संदेश तभी प्रभावी होगा जब गांव की महिला को यह महसूस हो कि उसके घर से निकला कचरा उसके रास्ते में, नाली में या खेत में वापस नहीं लौटेगा। जब उन्हें कचरा फेंकने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और जब बारिश में कचरा बहकर खेतों और जलस्रोतों तक नहीं पहुंचेगा, तभी स्वच्छता लोगों के जीवन का हिस्सा बनेगी।

इस समस्या का एक दूसरा पहलू जागरूकता का भी है। ग्रामीणों में से कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। कुछ घरों में कूड़ेदान दिए जाने के बाद भी कचरा नालियों में फेंकने की बात सामने आती है। लेकिन केवल लोगों को दोष देने से समस्या हल नहीं होगी। यदि घर से कचरा अलग करने की सलाह दी जाती है तो उसके बाद उसे उठाने, छांटने और निस्तारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। मैगड़ी स्टेट की कहानी किसी एक गांव की समस्या भर नहीं है। यह उस सवाल की ओर इशारा करती है जो ग्रामीण भारत के सामने अभी भी खड़ा है कि क्या स्वच्छता केवल लोगों के व्यवहार बदलने से आएगी या उसके लिए ऐसी स्थानीय व्यवस्था भी बनेगी जो लोगों को स्वच्छ रखने में सक्षम बनाए? यह सच है कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता को एक बड़े जन-अभियान का रूप दिया है। लेकिन अब अगला कदम उस अभियान की पहुंच को गांव के आखिरी छोड़ तक पहुंचाने की जरूरत है।

दोनों हाथों से देश और प्रदेश को लूट रही भाजपा सरकार- डॉ अजय सिंह चौटाला



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाजपा सरकार का आमजन के हितों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार दोनों हाथों से देश और प्रदेश की जनता को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का वक्त आ गया है। डॉ चौटाला ने आह्वान करते हुए कहा कि जेजेपी की महेंद्रगढ़ रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर घमंड में चूर भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम करे। शुक्रवार को जेजेपी प्रमुख रोहतक और हांसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू थे। इससे पहले उन्होंने छह दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जेजेपी की जन-जन अधिकार रैली का न्यौता दिया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ बड़ा धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार अब किसानों के हाथों में चवन्नी थमा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं और गन्ने के दाम में नामात्र बढ़ोतरी करना किसानों के हित में कतई नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए और इसके लिए गेहूं व गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पुनर्विचार करके बढ़ाना चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि आज किसान शुगर मिलों को ताला लगाकर अपना विरोध जता रहे है और सरकार को किसानों की आवाज को प्राथमिकता से सुनना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार द्वारा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि सरकार ब्यौरा दें कि आज वे कौन-सी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है ? उन्होंने कहा कि बाजरे का एमएसपी करीब 2900 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन ऐसी कोई भी मंडी नहीं जहां किसान ने बाजरे को 2200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बेचा हो। इसी तरह किसानों को धान में नमी के नाम 600 रुपए तक की कटौती करके लूटा जा रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि सीएम नायब सैनी हरियाणा के धरातल से अनजान है, वे सिर्फ पंजाब दौरों का रिकॉर्ड बनाने में व्यस्त है। प्रदेश में सीएम के नदारद होने के चलते मंडियों में किसानों के बुरे हाल है और हरियाणा के लोग खराब कानून व्यवस्था से परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न ही कोई नया निवेश आया है। भाजपा सरकार केवल झूठा प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। इस अवसर पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा, पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, वरिष्ठ नेता धर्मबीर सिहाग, रविंद्र सांगवान आदि ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रैली की तैयारियों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अनेक युवाओं ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की।

पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो, किसानों को सब्सिडी मिलने में न हो देरी : नायब सिंह सैनी

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की हर बूंद का सही और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना समय की मांग है। खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। इसी दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इस तकनीक का लाभ समय पर मिले और सब्सिडी जारी करने में देरी न हो। इसके लिए सब्सिडी की प्रक्रिया सरल की जाए, लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य



सचिव अनुराग अग्रवाल, मिकाडा के प्रशासक बीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा, संयुक्त निदेशक राजेश यादव तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड (एमआईएफ) के अंतर्गत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

बैठक में बताया गया कि 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

सब्सिडी जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में करीब 120 दिन का समय लगता है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल बनाया जाए और चरणों तथा समय को न्यूनतम संभव स्तर तक लाया जाए, ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके। उन्होंने लंबित आवेदनों का निपटारा भी तेजी से करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसान का निर्धारित अंशदान शुरुआती चरण में ही जमा हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसान का अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और आंकड़ों के सुचारू आदान-प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों की ई-केवाईसी स्वतः हो सके। साथ ही हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को भी मिकाडा के पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष प्रयासों और योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करके प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल खेती का दायरा बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने मौजूदा वॉटरकोर्स पॉलिसी की समीक्षा कर इसमें आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए, ताकि इसे अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और किसान हितैषी बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से पहले से पूरी हो चुकी एसटीपी परियोजनाओं में किसानों से सहयोग लेने पर विचार करने को कहा। ताकि इनके संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जिससे उनकी दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मिकाडा के अधिकारियों ने बैठक में बजट आवंटन को लेकर भी चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने वॉटरकोर्स और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं, दोनों के लिए बजट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मिकाडा की गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए, ताकि पात्र कार्यों को विभिन्न योजनाओं के संसाधनों के समन्वय से पूरा किया जा सके।

सरस्वती नदी का पुनर्जीवन करतारपुर कॉरिडोर और राम मंदिर जितना महत्वपूर्ण : गजेंद्र सिंह शेखावत

अनप्लग इंडिया

यमुनानगर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा में सरस्वती नदी के पुनर्जीवन प्रयासों की सराहना करते हुए इसे देश के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का कार्य बताया। उन्होंने कहा कि सरस्वती का पुनर्जीवन, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना और अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की पुनर्स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गौरव के प्रतीक हैं। शेखावत शुक्रवार को यमुनानगर जिले में आयोजित श्री कपाल मोचन-आदि बद्री मेले के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने गुरु घर में माथा टेका और हवन-यज्ञ के साथ मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रिमोट का बटन दबाकर करीब 187 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इनमें 16 नए जन औषधि केंद्र, 11 जलघरों में नए टैंकों का निर्माण तथा जगाधरी शहर की पुरानी सीवर लाइन के पुनर्वास कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने मोबाइल पुलिस बूथ का उद्घाटन करने के साथ मेले में लगाई गई प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी अवलोकन किया।

सरस्वती का लुप्त होना भारत के सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा-गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरस्वती नदी का विलुप्त होना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उन्होंने सरस्वती नदी के पुनर्जीवन को देश की ऐतिहासिक चेतना और गौरव की पुनर्स्थापना से जोड़ते हुए कहा कि भारत आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवंत करने के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने भगवान श्रीराम के मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि लाखों लोगों के बलिदान और सदियों के संघर्ष के बाद देश अपने गौरवशाली सांस्कृतिक दौर की ओर बढ़ रहा है। उनके अनुसार, भारत का सौभाग्य एक बार फिर उदित हो रहा है और देश अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहा है।

कपाल मोचन तीर्थ आत्मशुद्धि और साझा संस्कृति का केंद्र-केंद्रीय मंत्री ने कपाल मोचन तीर्थ को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रा का उद्देश्य केवल किसी स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाना और नए संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ना है।

उन्होंने पौराणिक मान्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान शिव भी ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए कपाल मोचन में स्नान करने आए थे। इस कथा का संदेश है कि मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं,

दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्साह के साथ संपन्न

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। जिला प्रशासन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुरुग्राम की ओर से 19 एवं 20 नवंबर को राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर-14 में आयोजित दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव शुक्रवार को उत्साह एवं सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। संस्थान के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस महोत्सव में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कला, सांस्कृतिक प्रतिभा एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। महोत्सव में समूह लोकगीत, समूह लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, समूह वाद्य यंत्र वादन, चित्रकला एवं कविता सहित छह विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ भारतीय लोक संस्कृति, कला एवं साहित्य से जुड़ने का अवसर मिला। महोत्सव का शुभारंभ 19 नवंबर को सोहना के विधायक तेजपाल तंवर ने किया था। इस अवसर पर डॉ. सुनील डबास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा महोत्सव जैसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। समापन समारोह में संस्थान के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने सभी अतिथियों, निर्णायक मंडल के सदस्यों, सहयोगी संस्थानों, शिक्षकों एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा सामने लाने और विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिला युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों में पेंटिंग विधा में देव पाठक ने प्रथम, वर्षा ने द्वितीय और रवि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में जानवी प्रथम, दिवांशी मिश्रा द्वितीय और अंशु गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। लोकगीत प्रतियोगिता में नंदनी गिरि ग्रुप ने प्रथम, वानी सिंह ग्रुप ने द्वितीय और विस्मय ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में खुशी ग्रुप प्रथम रहा। लोक नृत्य में सुमित भारती ग्रुप ने प्रथम, रजनी ग्रुप ने द्वितीय और मीनू ग्रुप ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में चिंटू ग्रुप प्रथम, शिवान्शिका ग्रुप द्वितीय और अमन मेहता ग्रुप तृतीय स्थान पर रहा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर-14, गुरुग्राम की कार्यवाहक प्रधानाचार्या सुनीता ढाका, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य देवानंद, राजकीय आईटीआई सोहना की प्रधानाचार्या सोनिया तक्षक, राजकीय आईटीआई (महिला), गुरुग्राम से सुनीत वत्स, आईटीआई गुरुग्राम के एपीओ डॉ. संतोष कुमार तथा राजकीय आईटीआई मौजाबाद के जीआई एवं प्रभारी विजयपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सीएम घोषणाओं एवं विभिन्न शिकायतों का प्राथमिकता से करें समाधान : एडीसी ज्योति



अनप्लग इंडिया

तावडू। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम घोषणाओं, सीएम विंडो एवं एसएसजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीसी ज्योति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो एवं एसएसजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निर्धारित समयावधि में समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निवारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए उसकी अनुपालन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनसे जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। जिन घोषणाओं से संबंधित कार्य लंबित हैं, उनमें आ रही बाधाओं को दूर करते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए। एडीसी ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए सभी अधिकारी जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहें और यह सुनिश्चित करें कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त शशि वसुंधरा, नगराधीश अप्रितम सिंह, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रदीप, एलडीएम पंकज सागर फलदू सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी फूल चंद मुलाना का निधन, नेताओं ने व्यक्त किया दुख

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी फूल चंद मुलाना का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 85 साल के थे और किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर नेताओं ने दुख जताया है। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हमारे अजीज साथी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं हमारी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे चौ. फूल चंद मुलाना के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत आहत हूं। प्रदेश के विकास में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके जाने से मुझे निजी क्षति हुई है और मैंने अपना एक अनमोल व कर्मठ सहयोगी खो दिया है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें।' कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,



'हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी फूलचंद मुलाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका निधन कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके पुत्र एवं सांसद वरुण चौधरी सहित समस्त शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को संबल प्रदान करें। ' कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री, फूल चंद मुलाना के निधन की खबर से दिल व्यथित है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए ये भारी क्षति है। समाज के वंचितों के लिए उनका योगदान सदा स्मरण किया जाएगा। '

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारे प्रधान जी हमसे दूर चले गए! हमारे परिवार के बड़े, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौ. फूल चंद मुलाना के निधन की खबर दुखद है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सादगी के साथ जनसेवा में समर्पित कर दिया। प्रदेश के विकास में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उनके जाने से एक अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। '

बता दें कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चौधरी फूलचंद मुलाना पंचकूला स्थित अपने घर पर थे। शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए अंबाला लाया जाएगा।

फूल चंद मुलाना हरियाणा कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक प्रदेशाध्यक्ष रहे। उन्होंने करीब साढ़े 6 साल तक पार्टी की कमान संभाली। वे मुलाना विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे। उनके बेटे वरुण चौधरी अंबाला से कांग्रेस सांसद हैं, जबकि बहू पूजा चौधरी मुलाना से विधायक हैं। वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिता के निधन की जानकारी दी।

राहुल गांधी का किरदार बन गया है विदेशों में भारत को नीचा दिखाना : अनिल विज



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ''विदेशों को ताली और भारत को गाली'' देना राहुल गांधी जी का किरदार बन गया है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तो देश को नीचा दिखाने में कोई कौर-कसर नहीं छोडते हैं।

विज ने आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि जब विदेशों से मंत्री भारत आते हैं और मंच से भारत की निंदा करते हैं तो ये (विपक्ष/राहुल गांधी) खिलखिलाकर हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का किरदार हो गया है कि दुनिया में भारत को नींचा दिखाओ। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि जब विपक्ष/राहुल गांधी की सरकार थी तो श्रद्धांजलियां देकर चली जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, तो तत्कालीन सरकारों के दौरान कोई कदम नही उठाया गया है और कदम उठाया तो केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि जब-जब भी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है तो पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा है और फिर मारेंगें, अगर वे अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आएंगे। वहीं, अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना के निधन पर दुख जताया और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि फूलचंद मुलाना ने काफी लंबे समय तक राजनीति की और मंत्री भी रहे।

वीडियो बनाने से किसान नहीं बचेगा, जींद आकर दिखाओ-रतन मान

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। आज मैं गन्ने के खेत से, किसान की जमीन से, किसान की मिट्टी से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे खड़ा ये गन्ना सिर्फ फसल नहीं है, ये किसान की मेहनत है, उसके बच्चों की फीस है, उसके घर का चूल्हा है, उसकी पगड़ी की इज्जत है। यह बात भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीडिया को जारी बयान में कही।

कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी की थी। वो वीडियो किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं थी, वो वीडियो किसी संगठन के खिलाफ नहीं थी। वो वीडियो पूरे हरियाणा के किसान के हक के लिए थी। उसमें मैंने साफ कहा था कि अब वक्त आ गया है, सबको एक होना पड़ेगा। उसके बाद गुरनाम चढ़ूनी जी की तरफ से एक वीडियो आई। उन्होंने कहा - फलां आदमी से बात कर लो, रामपाल चाहल से बात कर लो। मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ - गुरनाम जी, ये आंदोलन कमरे में बैठकर होगा या मैदान में होगा ?

आंदोलन कमरे में नहीं, मैदान में होता है

गुरनाम जी, आपने कहा किसी एक आदमी से बात कर लो।

मैं पूछता हूँ - एक आदमी से बात करके क्या होगा ? क्या एक आदमी गन्ने का रेट तय कर देगा ? क्या एक आदमी सरकार को झुका देगा ? क्या एक आदमी 20 लाख किसानों की आवाज बन जाएगा ? किसान का आंदोलन किसी एक आदमी की जागीर नहीं है। ये आंदोलन लाखों किसानों के पसीने से बना है। इसलिए बात होगी तो सबके सामने होगी। बात होगी तो एसकेएम के सभी साथियों के सामने होगी। बात होगी तो किसान के सामने होगी, मीडिया के सामने होगी, खुले मंच पर होगी। पीठ पीछे की बात, कमरे की बात, फोन की बात - इससे किसान का भला कभी नहीं हुआ। हमने देखा है, जब भी किसान की बात कमरे में हुई है, किसान को ही ठगा गया है।

इसलिए मैं साफ कहता हूँ - मुझे छिपकर बात नहीं करनी, मुझे खुलकर बात करनी है।

निमंत्रण नहीं, चुनौती है - कल जींद आओ

गुरनाम जी, मैं आपको फिर से, पूरी इज्जत के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ निमंत्रण दे रहा हूँ।

21 नवंबर को जींद शुगर मिल में आइए

वहाँ कोई छोटी मीटिंग नहीं है। वहाँ पूरे एसकेएम के लोग होंगे। वहाँ हर जिले से किसान आएगा। वहाँ गन्ने को लेकर महापंचायत होगी। वहाँ गन्ने के रेट, गन्ने की पेमेंट, मिल के मुद्दे, किसान की लूट - सब पर खुलकर बात होगी। वहाँ आइए।



मंच पर भी एक हो जाएंगे। मंच के नीचे भी बैठकर बात कर लेंगे। अलग से भी बैठ लेंगे। जैसा आप चाहो, वैसा कर लेंगे।

लेकिन आइए जरूर।

क्योंकि अगर आप कल जींद नहीं आए, तो हरियाणा का किसान समझ जाएगा कि कौन लड़ना चाहता है और कौन वीडियो बनाकर घर बैठना चाहता है।

गन्ना किसान आज सबसे ज्यादा लुट रहा है

साथियों, आज बात सिर्फ गुरनाम जी की नहीं है, बात गन्ने की है। आज हरियाणा का गन्ना किसान बर्बाद हो रहा है। मिलें देर से चल रही हैं। गन्ना खेत में सूख रहा है। रेट नहीं बढ़ रहा। पेमेंट अटकी हुई है। लागत दिन-ब-दिन बढ़ रही है। डीजल महंगा, खाद महंगी, मजदूरी महंगी, लेकिन गन्ने का रेट वही का वही। किसान कर्ज में डूब रहा है। किसान की ट्रॉली मिल के बाहर खड़ी है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकार कहती है - हम किसान के साथ हैं। मिल मालिक कहता है - हम मजबूर हैं। नेता कहते हैं - हम लड़ रहे हैं। लेकिन जमीन पर किसान अकेला है। इसीलिए कल जींद की महापंचायत सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये गन्ना किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कल हम सब एक नहीं हुए, तो सरकार यही समझेगी कि किसान बंटा हुआ है। और बंटा हुआ किसान कभी जीत नहीं सकता।

एकता ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है

मैं आज फिर कहता हूँ - मेरे लिए कोई संगठन बड़ा नहीं है, कोई पद बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। मेरे लिए सिर्फ किसान बड़ा है। एसकेएम बना ही इसलिए था कि सब एक साथ लड़ें। अगर हम फिर अलग-अलग वीडियो बनाकर, अलग-अलग बयान देकर लड़ेंगे, तो सरकार हंसेगी और किसान रोएगा। मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मैंने हमेशा कहा है - आओ, एक हो जाओ। लेकिन एकता का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी बोले और बाकी सब सुनें। एकता का मतलब है - सब बैठें, सब बोलें, सबकी सुनें, और फिर एक फैसला लें। कल जींद में वही होगा। वहाँ सबकी सुनी जाएगी। वहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा। वहाँ सिर्फ किसान होगा।

सरकार को भी साफ संदेश - अब बहाना नहीं चलेगा

इस प्रेस नोट के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को भी साफ संदेश देना चाहता हूँ।

सरकार, अब ये मत कहना कि किसान संगठनों में फूट है। कल हम सब जींद में एक मंच पर होंगे। अब ये मत कहना कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ सकता। जब हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ सकता ? अब ये मत कहना कि मिलों के पास पैसा नहीं है। मिलें किसान के पसीने से चल रही हैं। अगर मिल चलेगी, तो किसान की पेमेंट पहले देनी होगी। किसान अब भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। और हक मांगने के लिए किसान को सड़क पर उतरना पड़ा, तो वो उतरेगा भी।

अंतिम अपील - कल का दिन इतिहास बनाएगा

अंत में मैं हरियाणा के हर किसान से, हर जवान से, हर मजदूर से, हर सरपंच से, हर पंच से अपील करता हूँ - कल 21 नवंबर को जींद शुगर मिल पहुंचो। अपनी ट्रॉली लेकर आओ, अपने साथियों को लेकर आओ। ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे बच्चों के भविष्य की है। और गुरनाम जी, आपसे फिर कहता हूँ - आइए। मंच आपका इंतजार करेगा। किसान आपका इंतजार करेगा। अगर आप आए, तो किसान की जीत होगी। अगर आप नहीं आए, तो भी किसान की जीत होगी, क्योंकि किसान अब रुकने वाला नहीं है।

संक्षिप्त डायरी

नमो घाट और सरायमोहना के पास होंगे सीआरपीएफ के दो बेस, मिली जमीन

अनप्लग इंडिया

वाराणसी । काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा को लेकर नया खाका तैयार किया गया है। इसके मुताबिक नमो घाट और सरायमोहना के पास सीआरपीएफ के दो बेस होंगे। इसके लिए सीआरपीएफ को 90 साल के लिए जमीन मिली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो नए बेस बनाकर बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था अचूक की जाएगी। आदिकेशव घाट के पास सरायमोहना (अभिलेखों में सरैताबाद) और नमो घाट के पास किला कोहना (गोवर्द्धन धाम मंदिर के ऊपर वाला क्षेत्र) में 4.19 एकड़ सरकारी जमीन अगले 90 साल तक सीआरपीएफ के पास ही रहेगी। विश्वनाथ धाम परिसर में किसी भी आपात स्थिति में कम से कम समय में सुरक्षाकर्मी एक्शन ले सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से अब सीआरपीएफ को धाम में स्थायी रूप से मुस्तैद करने का फैसला लिया गया है। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा। बिना किसी खतरे के दर्शन की व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। तहसील सदर स्थित ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में 4.19 एकड़ सरकारी भूमि गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी। इसकी एक बटालियन पहाड़िया में पहले से ही है। चंदौली के चकिया में इसका मुख्यालय है। बाबा विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में पहली बार सीआरपीएफ की एक टुकड़ी लगाई गई थी। वहीं, शहर में कई जगहों पर हुए आतंकवादी विस्फोट के बाद साल 2007 में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में लगाई गई थी। वहां पहले से 40वीं बटालियन की तैनाती है। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि इस निर्णय से धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी। साथ ही आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। एक्शन लेने के समय में कमी आएगी। स्तरीय और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण में 10 दिन में कार्रवाई, गंगा से दूरी पर मांगा स्पष्टीकरण

अनप्लग इंडिया

वाराणसी अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण में 10 दिन में कार्रवाई का आदेश दिया गया। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी से निर्माण पूरा हो सकता है। वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी से निर्माण पूरा हो सकता है। बाद में उसे हटाने की नौबत आई तो सरकारी धन बर्बाद होगा। सुनवाई में सामने आया कि उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने पार्किंग परियोजना के लिए एनएमसीजी से पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देने पर मिशन ने 28 अक्तूबर को प्रस्ताव वापस कर दिया था। एनएमसीजी ने 19 नवंबर को जारी पत्र में यह जानकारी दी। मिशन ने जिला गंगा समिति और वाराणसी के जिलाधिकारी को भी निर्माण की स्थिति, आवश्यक अनुमतियों और शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।जज प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने आरोप लगाया कि गंगा तट पर स्थायी निर्माण पर्यावरणीय प्रावधानों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2012 के आदेश के विपरीत है। उस आदेश में गंगा के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के भीतर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने गंगा प्राधिकरण आदेश, 2016 के उस प्रावधान का भी हवाला दिया जिसमें नदी और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है। एनजीटी ने एनएमसीजी से तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। जिलाधिकारी से उसी दिन संपर्क करने को कहा पीठ ने कहा कि जिला गंगा संरक्षण समिति सीधे एनएमसीजी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। वाराणसी के जिलाधिकारी इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। एनएमसीजी के अधिवक्ता को निर्देश दिया गया कि वह तत्काल जिलाधिकारी वाराणसी से संपर्क स्थापित करें और उसी दिन उनसे बात करें ताकि मामले में जल्द से जल्द विधि के अनुसार निर्णय लिया जा सके।

सुनवाई की शुरूआत में पीठ ने निर्माण को सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ा बताते हुए निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति और गंगा नदी से उसकी दूरी स्पष्ट करने को कहा। इस संबंध में सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फोटोग्राफ और उपलब्ध साक्ष्यों के माध्यम से निर्माण स्थल की स्थिति न्यायाधिकरण के सामने रखी। उन्होंने कहा कि निर्माण गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में हो रहा है। इसे सामान्य सार्वजनिक निर्माण मानकर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

सहालग में होंगी 2200 शादियां, 600 करोड़ के पार होगा कारोबार; कल से घरों में बजेगी शहनाई

अनप्लग इंडिया

वाराणसी कल से घरों में शहनाई बजेगी। लगन को लेकर मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और होटल फुल हो गए हैं। इस बार 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच विवाह के मुहूर्त हैं। चातुर्मास के समापन के साथ ही शुक्रवार (देवोत्थान एकादशी) से मांगलिक कार्यों की शुरूआत होने जा रही है। इसके साथ ही काशी के बाजारों में सहालग की जबरदस्त रौनक लौट आई है। इस बार 13 दिनों के लग्न मुहूर्त में 2200 से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है। कारोबारियों के मुताबिक, 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच शादी-ब्याह इस सीजन से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होगा।वाराणसी टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता बताते हैं कि सहालग के लिए शहर के भीतर स्थित सभी मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और होटल पहले ही फुल हो चुके हैं। स्थिति यह है कि अब लोगों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए शहर की सीमा से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण और बाहरी इलाकों में भी लॉन या गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिल पा रही है। लॉन संचालक वीरेंद्र पटेल बताते हैं कि जिन परिवारों ने पहले से बुकिंग नहीं कराई थी, उन्हें वैवाहिक आयोजन स्थल तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सराफा, ऑटोमोबाइल और कैटरिंग सेक्टर में बंपर उछाल

वैवाहिक सीजन के चलते शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में खरीदारी तेज हो गई है। इस 600 करोड़ रुपये के कारोबार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सराफा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की रहने वाली है। उदय बजाज ऑटो के डीलर यूआर सिंह के मुताबिक, गहनों और परिधानों के साथ-साथ उपहार में देने के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। शो रूम पर रेट और ऑफर्स पूछने के लिए दिन भर फोन बज रहे हैं। इसके अलावा कैटरिंग, टेंट, लाइटिंग, बैंड-बाजा और फ्लावर डेकोरेशन से जुड़े कारोबारियों के पास भी काम की भरमार है।

रूप लाल को पड़ चुका ब्रेन स्ट्रोक, कार्यालय पहुंचे पीड़ित, बोले- फंड के लिए दौड़ाया जा रहा

अनप्लग इंडिया



कानपुर। छावनी परिषद में सीबीआई के छापे के दौरान जहां रिटायर सफाई नायक रूप लाल के ब्रेन स्ट्रोक व हृदय रोग से पीड़ित होने की बात सामने आई है। वहीं, कार्रवाई की सूचना पर रात में शुक्लागंज निवासी आकाश कुमार यादव और सौरभ धानविक सहित अन्य पीड़ित कार्यालय पहुंचे और फंड व नौकरी के लिए दौड़ाए जाने की पीड़ा बताई। कानपुर छावनी परिषद कार्यालय में सीबीआई के छापे के दौरान कार्यालय के पास मौजूद कुछ कर्मियों और उनके परिजन ने बताया कि सफाई नायक के पद से सेवानिवृा रूप लाल 10 साल से अपनी पेंशन और फंड के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी तनाव के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। इसके बाद हृदय की भी बीमारी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने घूस की रकम देने में असमर्थता जताई। छापे का पता चलते ही रात में शुक्लागंज निवासी आकाश कुमार यादव, सौरभ धानविक कार्यालय के बाहर पहुंचे। आकाश ने बताया कि उसके पिता रमेश चंद्र यादव छावनी परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। 27 अक्तूबर 2018 को उनका निधन हो गया था। उनका पांच लाख रुपये फंड बकाया है। इस धनराशि और मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी के लिए वह तभी से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह सौरभ धानविक ने बताया कि 30 जून 2023 को उसकी दादी रामवती सेवानिवृा हुई थीं। उनको अभी तक फंड नहीं मिला है। सीबीआई के छावनी परिषद की अधिकारी वंदना को गिरफ्तार करने का पता चलने पर रात करीब साढ़े 12 बजे कुछ रिश्तेदार छावनी परिषद के बाहर पहुंचे। अनुमति मिलने के बाद वे परिषद के कार्यालय के अंदर गए और वंदना से मुलाकात की। सात साल में तीसरी बार फिर मारा छापा कैंटोनमेंट बोर्ड (छावनी परिषद) में सीबीआई ने बृहस्पतिवार को फिर से छापा मारा। सात साल में तीसरी बार सीबीआई यहां आई है। छह सितंबर 2023 को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने छावनी परिषद कार्यालय में छापा मारकर वरिष्ठ लिपिक और एक अन्य कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। भुगतान और पेंशन निर्धारण के लिए मांगी गई थी घूस 30 जून 2023 को सेवानिवृा हुई फेथफुलगंज निवासी रामवती से तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक धर्मेंद्र कुमार ने कर्मचारी आनंद कुमार के जरिये पीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित रकम दिलाने के एवज में 40 हजार की घूस मांगी थी।रामवती के नाती सौरभ धानुक ने बताया कि बकाया भुगतान और पेंशन निर्धारण के लिए घूस मांगी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने वरिष्ठ लिपिक और कर्मचारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दोनों जेल भेज दिए गए थे। दोनों निलंबित भी कर दिए गए थे। अभी भी दोनों निलंबित चल रहे हैं। वहीं, बताया गया कि 30 अगस्त 2019 को अवैध मोबाइल टॉवर और अतिक्रमण जांच के संबंध में सीबीआई की टीमों ने अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर कैंट बोर्ड कार्यालय में छापेमारी की थी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले गुनाहगार को 20 साल की सख्त सजा के साथ ही सुनाया गया 14 हजार का जुमानां



हमीरपुर (अनप्लग इंडिया ।) सिसोलर में 26 जुलाई को 2022 को 11 साल की नाबालिग छात्रा के घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने वाले गुनाहगार के खिलाफ पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर सिसोलर पुलिस ने गांव के ही मुल्जिम मान सिंह पुत्र भूरा यादव के खिलाफ मु0अ0सं0-113/2022 धारा-376एबी,452,506 आईपीसी सहित 5एम/6 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पॉक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम मान सिंह को धारा- 452,506 भा0द0सं0 व 6 पॉक्सो के तहत गुनाहगार मानते हुये 20 साल की सख्त सजा के साथ ही सुनाया 14 हजार का जुमार्ना। वहीं मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर सुरेश कुमार सैनी ने पूरी करते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी। जबकि अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रूद्र प्रताप सिंह ने दमदार पैरवी करते हुते अदालत से मुल्जिम को सख़्त सजा देने की मांग की थी।

23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट को नहीं मिले अपराध में शामिल होने के सबूत

अनप्लग इंडिया



अलीगढ़। अलीगढ़ में 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष सुनील की घटना में संलिप्तता और गैंग का सक्रिय सदस्य होने के आरोप साबित नहीं कर सका। करीब 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले के मामले में अलीगढ़ की विशेष न्यायालय ने सुनील को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष सुनील की घटना में संलिप्तता और गैंग का सक्रिय सदस्य होने के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी पेश नहीं हुआ। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) संजय कुमार यादव प्रथम ने 18 नवंबर को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के मुताबिक, पांच जनवरी 2003 को लक्ष्मी टॉकीज के बाहर साइकिल स्टैंड पर काम करने वाले संजय का कुछ दिन पहले साइकिल किराये पर देने को लेकर सुनील और बबलू से विवाद हुआ था। आरोप था कि शाम करीब आठ बजे संजय को टॉकीज के बाहर देखकर सुनील और बबलू ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे मारने के लिए फायरिंग की। मौके पर जुटी भीड़ ने संदीप कुमार उर्फ मोनू, सतेन्द्र उर्फ लालू और अजय कुमार को पकड़ लिया था, जबकि सुनील और बबलू भाग निकले थे। इस मामले में पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। इनमें पुलिसकर्मी और विवेचक के अलावा वादी संजय का भाई राकेश कुमार शामिल था। राकेश ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। मुकदमे के वादी संजय की वर्ष 2005 में मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने पाया कि सुनील के खिलाफ इस मुकदमे के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिहास भी साबित नहीं किया गया। न ही उसके गैंग का सदस्य होने या आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया। इन परिस्थितियों में अदालत ने सुनील को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149 और गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं, इसी मामले के तीन अन्य आरोपी संदीप, सतेन्द्र और अजय के खिलाफ सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संचालित की गई थी। अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने और पुलिस को फरारी रजिस्टर में नाम दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उनके अदालत में पेश होने या पकड़े जाने पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

फ्रेंड्स कॉलोनी में रास्ता बंद करने पर रोक, निगम ने लगाए लाल निशान; तीन दिन का अल्टीमेटम

अनप्लग इंडिया



आगरा। के शाहगंज स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में सार्वजनिक रास्ते पर तीन पिलर खड़े कर गेट लगाने की तैयारी को नगर निगम ने रुकवा दिया। निगम की टीम ने लाल निशान लगाकर संबंधित पक्ष को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। आगरा के शाहगंज स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में आम रास्ते पर पिलर खड़े कर गेट लगाने की तैयारी के बीच नगर निगम ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण पर लाल निशान भी लगाए। साथ ही संबंधित पक्ष को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। आरोप लगाया गया कि कॉलोनी के मकान संख्या 31-ए एमआईजी के सामने सार्वजनिक मार्ग पर तीन पिलर बना दिए गए थे। गेट लगाकर रास्ता बंद करने की तैयारी थी। स्थानीय निवासियों का आवागमन बाधित होने की आशंका थी। कॉलोनी के अध्यक्ष सुधीर टंडन और क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इसकी शिकायत की। अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अतिक्रमण चिह्नित करते हुए लाल निशान लगाए और चेतावनी दी कि दी गई समय सीमा में पिलर नहीं हटे तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं हैं। तय समय में कब्जा न हटने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

घर के पीछे तालाब में मिला भाजपा बूथ अध्यक्ष का शव, 31 साल की उम्र में मौत

अनप्लग इंडिया



आगरा। के मलपुरा क्षेत्र के कबूलपुर गांव में 31 वर्षीय भाजपा बूथ अध्यक्ष नागेंद्र का शव घर के पीछे तालाब में उतराता मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा-ग्वालियर रोड स्थित गांव कबूलपुर में बृहस्पतिवार को तालाब में डूबने से 31 वर्षीय भाजपा के बूथ अध्यक्ष की मौत हो गई। उनका शव घर के पीछे स्थित तालाब में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबूलपुर निवासी नागेंद्र बृहस्पतिवार देर रात किसी कार्यक्रम से अपने घर पहुंचे थे। मृतक के चाचा दारा सिंह ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद वह घर के पीछे स्थित तालाब के किनारे टहलने के लिए चले गए थे। मृतक के भाई करतार ने बताया कि करीब चार बजे उन्हें तालाब में नागेंद्र का शव उतराता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन उन्हें बाहर निकालकर उपचार के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नागेंद्र की मौत की खबर से पत्नी रोशनी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके दो पुत्रियां और एक पुत्र हैं। पिता वीरेंद्र सिंह खेती करते हैं। नागेंद्र सोलर पैनल का कार्य करते थे, वह राजनीति में भी सक्रिय थे। भाजपा के बरौली अहीर मंडल अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने बताया कि नागेंद्र 271 बूथ के अध्यक्ष थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।

सितारों की एक झलक को उमड़ा जनसैलाब, जिले में फिल्म की शूटिंग करने का वादा

अनप्लग इंडिया



वाराणसी अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा कि वह मुंबई जाकर फिल्म प्रोड्यूसर से जौनपुर में फिल्म की शूटिंग कराने की बात करेंगे। वहीं, अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा, 'नमस्ते जौनपुर, आई लव यू'। दोनों सितारों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बॉलीवुड सितारों की एक झलक पाने के लिए बृहस्पतिवार को मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज का मैदान प्रशंसकों से खचाखच भर गया। फिल्म गन मास्टर जी9 के प्रमोशन के लिए पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी, अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख और सह अभिनेता पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह का लोगों ने स्वागत किया। इमरान हाशमी ने जौनपुर में फिल्म की शूटिंग कराने का वादा किया तो मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि मुंबई जाकर प्रोड्यूसर से जौनपुर में फिल्म की शूटिंग कराने को कहूंगा। दोपहर बाद अभिषेक सिंह की अगुवाई में सितारों का काफिला शहर में दाखिल हुआ। पॉलीटेक्निक और वाजिदपुर तिराहे पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद काफिला जेसीज चौराहा, ओलंदगंज, चहारसू चौराहा और कोतवाली होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचा। सुबह 11 बजे से ही प्रशंसकों का जुटना शुरू हो गया था। मैदान भरने के बाद सड़क तक भीड़ लग गई। कई लोग छतों, दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर कार्यक्रम देखते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता सितारों के पहुंचते ही इमरान-इमरान के नारों से मैदान गूंज उठा। मंच से इमरान ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कहा कि जौनपुर के लोगों का इतना प्यार और उत्साह देखकर दिल खुश हो गया। यहां के लोगों का प्यार कभी नहीं भूल सकता। जल्द दोबारा जौनपुर आने का भी वादा किया। वहीं, अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने नमस्ते जौनपुर, आई लव यू कहकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने यहां के अपनापन और उत्साह की सराहना की। सह अभिनेता अभिषेक सिंह ने युवाओं से 27 नवंबर को सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील की। कलाकारों ने फिल्म के संवाद सुनाए और प्रशंसकों से बातचीत की। इमरान ने उनके साथ सेल्फी भी ली। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड सितारों की एक झलक पाने के लिए मोहम्मद हसन कॉलेज के मैदान में सुबह 11 बजे से ही प्रशंसकों का पहुंचना शुरू हो गया था। समय बीतने के साथ युवाओं की भीड़ बढ़ती गई। हालांकि, कार्यक्रम स्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं होने से प्रशंसकों को परेशानी उठानी पड़ी। भीड़ में एक युवती गश खाकर गिर पड़ी। अभिनेता इमरान हाशमी शाम करीब साढ़े चार बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वह लगभग आधे घंटे तक वहां रहे। अपने पसंदीदा अभिनेता को सामने देखकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई प्रशंसक मोबाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने में जुटे रहे। कुछ युवतियां इमरान हाशमी की तस्वीर लेकर भी पहुंची थीं। सितारों की एक झलक पाने के लिए युवा काफी देर तक मैदान में डटे रहे।

जैकी श्रॉफ ने संघर्ष के दिनों में उधार लिए पांच रुपये लौटाए, अर्चना पूरन सिंह को दिए 500 रुपये

बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने बेबाक अंदाज और दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। उनके संघर्ष के दिनों से जुड़ा एक पुराना किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस कहानी में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी शामिल हैं। दरअसल, जैकी श्रॉफ ने कई साल पहले अर्चना से पांच रुपये उधार लिए थे। अब उन्होंने यह रकम दस गुना नहीं, बल्कि सौ गुना करके लौटाई है। अभिनेता ने पांच रुपये के बदले अर्चना को 500 रुपये दिए। इस घटना से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है। यह किस्सा कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के एक पुराने एपिसोड से जुड़ा है। उस कार्यक्रम में अर्चना पूरन सिंह ने जैकी श्रॉफ के संघर्ष के दिनों की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि जब दोनों अपने करियर में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब वे नेपियन सी रोड पर आसपास रहते थे। जैकी उस समय तीन बत्ती इलाके में रहते थे। अर्चना ने बताया कि जैकी का स्वभाव हमेशा से मददगार रहा है और वह जरूरतमंद लोगों की परेशानी देखकर उनकी सहायता करने के लिए आगे आ जाते थे।

अर्चना के मुताबिक, जब जैकी के सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ जाता और अपनी परेशानी बताता, तो अभिनेता तुरंत उसकी मदद करना चाहते थे। ऐसे में वह कई बार उनसे एक रुपया मांग लेते थे। अर्चना ने बताया कि उन्हें उस समय समझ नहीं आता था कि जैकी उनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं, लेकिन वह उन्हें एक रुपया दे देती थीं। इसके बाद जैकी उस जरूरतमंद व्यक्ति को पैसे दे देते थे और बदले में उसे दुआएं मिलती थीं। अर्चना ने बताया कि उस समय दोनों ही संघर्ष कर रहे थे। उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन जैकी का दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर देते थे। इसी वजह से कई बार उनके पास खुद के खर्च के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। जब जैकी श्रॉफ ने यह पुराना वीडियो देखा, तो उन्होंने अर्चना को पांच रुपये के बदले 500 रुपये लौटाए। अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पांच रुपये के बदले 500 रुपये। इस पर अर्चना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह कपिल के शो में उनकी पहली कमाई है।

जैकी ने इस दौरान अपनी पुरानी आदत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें शूटिंग के बाद पैसे मिलते थे, तो रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करने में वह रकम खर्च हो जाती थी। कभी किसी का घर जल गया होता, तो कभी किसी के परिवार में शादी होती या किसी के घर बच्चे का जन्म होने वाला होता। ऐसे मौकों पर वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते थे। अभिनेता ने बताया कि कई बार प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को भी पता होता था कि उस दिन उन्हें भुगतान मिलने वाला है। लेकिन घर पहुंचने तक वह पैसे लोगों की मदद में खर्च कर चुके होते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अर्चना से पैसे उधार लेने पड़ते थे। यह पुराना किस्सा एक बार फिर जैकी श्रॉफ की दरियादिली और अर्चना के साथ उनके पुराने रिश्ते को सामने लाता है।



महेला जयवर्धने बने जीएमआर स्पोर्ट्स में क्रिकेट डायरेक्टर

डब्ल्यूपीएल का कामकाज देखेंगे

नई दिल्ली । श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को जीएमआर स्पोर्ट्स ने क्रिकेट डायरेक्टर बनाया है। जयवर्धने इस भूमिका में विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी, आईएलटी20 में दुबई कैपिटल्स और द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव के क्रिकेट



कामकाज देखेंगे। जीएमआर स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम के पोर्टफोलियो में, जयवर्धने क्रिकेट ऑपरेशन, टैलेंट की पहचान, प्लेयर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देंगे और हर फ्रेंचाइजी में लीडरशिप, हेड कोच और क्रिकेट मैनेजमेंट टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। वह हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर जाइल्स व्हाइट के साथ भी काम करेंगे, ताकि ग्रुप की टीमों के बीच नॉलेज, एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिस साझा कर सकें। इस नियुक्ति से डब्ल्यूपीएल जीतने की कोशिश कर रही दिल्ली कैपिटल्स को मजबूती मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स 2023 में शुरू हुए डब्ल्यूपीएल की पांच फाउंडिंग टीमों में से एक है। अब तक टूर्नामेंट के सभी चार एडिशन में फाइनल में पहुंची टीम हर बार रनर-अप रही है। अपनी नियुक्ति के बाद जयवर्धने ने शनिवार को दिए एक बयान में कहा, 'दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत पहचान है और महिला क्रिकेट के भविष्य के लिए एक रोमांचक विजन है। मुझे डब्ल्यूपीएल टीम के लिए क्रिकेट डायरेक्टर का रोल निभाने में बहुत खुशी हो रही है। इस कॉम्पिटिशन में महिलाओं के खेल के भविष्य को आकार देने की बहुत ज्यादा क्षमता है। मैं टैलेंटेड खिलाड़ियों के एक स्थापित ग्रुप और एक अनुभवी सपोर्ट टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।'

हांगकांग ओपन 2026

सात्विक-चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में, रक्षिता बाहर

हांगकांग । भारत की सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शुक्रवार को चीन के हू के युआन और लिन जियांग यी की जोड़ी को हराकर हांगकांग ओपन 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को 21-12, 13-21, 21-16 से हराकर जीत दर्ज की। वे दूसरा गेम हार गए, लेकिन वापसी करते हुए तीसरा गेम जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय जोड़ी ने 13 मिनट में 21-12 से पहला गेम जीत लिया। दूसरा गेम ज्यादा कड़ा था और 4-4 की बराबरी के बाद दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई। फिर स्कोर 9-9



से बराबर हो गया। हू और लिन ने 13-11 से बढ़त बनाई और 15-11 पर पहुंचने के बाद इसे 21-13 से जीत लिया। भारतीयों ने तीसरे गेम में जबरदस्त वापसी की और इंटरवल तक 11-7 से आगे थे। उन्होंने जीत का सिलसिला बनाए रखा और 15-9 तथा 17-10 से आगे हो गए। हालांकि, चीनी जोड़ी ने आखिर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सात्विक और चिराग ने अपना संयम बनाए रखते हुए गेम 21-16 से जीतकर आखिरी चार में जगह बनाई।

दूसरी ओर, भारत की रक्षिता रामराज महिला एकल क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से 53 मिनट में 19-21, 16-21 से हारकर बाहर हो गईं। 19 साल की भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, जिसमें स्कोर 13-13 से बराबर रहा। चोचुवोंग 17-15 से आगे हो गईं, लेकिन रक्षिता ने वापसी करते हुए 17-17 से बराबरी कर ली। हालांकि, थाई शटलर ने धैर्य बनाए रखते हुए 21-19 से गेम जीत लिया।

वेलिंगटन टेस्ट: दूसरे दिन का खेल समाप्त
भारत का स्कोर 1 विकेट पर 159 रन

जायसवाल शतक से चूके



निकोलस 113

वेलिंगटन । भारत ने बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के समय 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए थे। केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। शुरुआत धीमी रही, लेकिन एक बार लय मिलने के बाद भारतीय ओपनरों ने मैदान के चारों ओर रन बनाए। जायसवाल बेहद आक्रामक रहे। बाएं हाथ का यह युवा सलामी बल्लेबाज शतक से चूक गया। जायसवाल 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल को मैट हेनरी ने आउट किया। आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 27.5 ओवर में 130 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। केएल राहुल 116 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए पडिक्कल 35 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 29 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की पहली पारी के स्कोर से अभी भी 209 रन पीछे है।

इससे पहले दूसरे दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 243 रन से की थी। और ग्लेन फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद थे। फिलिप्स ने शानदार शतक लगाया। वह 216 गेंदों पर 118 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप्स और निकोलस ने छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी की।

फिलिप्स का विकेट गिरने के बाद भी निकोलस ने एक छोर थामे रखा और नाथन स्मिथ (14) के साथ सातवें विकेट के लिए 32, काइल जैमिसन (11) के साथ आठवें विकेट के लिए 25 और जैकब डफी (4) के साथ दसवें विकेट के लिए 20 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 368 रन तक पहुंचाया। हेनरी निकोलस 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, आकाशदीप ने 3 विकेट, अंशुल कंबोज ने 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर को विकेट नहीं मिला।

निकोलस 175 पर नाबाद रहे, फिलिप्स ने भी लगाया शतक

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 368 रन

वेलिंगटन । भारत के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोलस और ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन की शुरुआत 5 विकेट पर 243 रन से की थी।

निकोलस 113 और ग्लेन फिलिप्स 94 रन पर नाबाद थे। फिलिप्स ने शानदार शतक लगाया। आकाशदीप की गेंद पर बोल्ड होने से पहले फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रन बनाए। फिलिप्स और निकोलस ने छठे विकेट के लिए 216 रन की अहम साझेदारी कर स्कोर को 286 तक पहुंचाया। फिलिप्स का विकेट गिरने के बाद भी निकोलस ने एक छोर थामे रखा और नाथन स्मिथ (14) के साथ सातवें विकेट के लिए 32, काइल जैमिसन (11) के साथ आठवें विकेट के लिए 25 और जैकब डफी (4) के साथ दसवें विकेट के लिए 20 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 368 रन तक पहुंचाया।

हेनरी निकोलस 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से 175 रन बनाकर नाबाद रहे। निकोलस का यह 12वां टेस्ट शतक है और इस वेन्यू पर लगाया 5वां शतक है।

ग्लेन फिलिप्स ने की रोहित शर्मा की बराबरी

हासिल की असाधारण उपलब्धि

वेलिंगटन । न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने वेलिंगटन में भारत के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन (शुक्रवार) शतक लगाया। फिलिप्स ने 118 रन की पारी खेली। इस शतक के साथ ही फिलिप्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ग्लेन फिलिप्स एक ही कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक ही कैलेंडर ईयर में किसी टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले फिलिप्स दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले यह कीर्तिमान भारत



के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी हासिल कर चुके हैं। फिलिप्स ने जनवरी 2026 में इंदौर में भारत के खिलाफ हुए वनडे में 106 रन की पारी खेली थी। वहीं, भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू टी20 सीरीज के चौथे मैच में उन्होंने 107 रन बनाए थे। मौजूदा टेस्ट में खेली गई 118 रन की पारी से उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में एक ही टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाया था। उस समय वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं, और भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहा है। फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 232 रन बनाए हैं। वहीं, 16 वनडे की 12 पारियों में 1 शतक की बदौलत 342 रन बनाए हैं। टी20 फॉर्मेट में फिलिप्स का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली है। भारत के खिलाफ 22 टी20 मैचों की 20 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 657 रन बनाए हैं।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 897, निफ्टी 286 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को जोरदार तेजी के साथ कारोबार का समापन किया। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से आया है। जिससे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच। लगातार दूसरे सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए, बाजार ने निवेशकों को बड़ी राहत दी। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 897.96 अंक की प्रभावशाली बढ़त के साथ 83,919.71 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 286.30 अंक की छलांग लगाकर 25,800.60 पर पहुंचा। दिन के कारोबार के दौरान भी दोनों प्रमुख सूचकांकों ने अपने उच्चतम स्तरों को हासिल किया। सेंसेक्स ने 1,016.21 अंकों की उछाल के साथ 84,037.96 का इंट्रा-डे हाई दर्ज किया, जबकि निफ्टी 50 ने 294.5 अंकों की तेजी के साथ 25,808.80 के उच्चतम स्तर को स्पर्श किया। यह दिखाता है कि बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है। आज के कारोबार में, निफ्टी 50 इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों में 5.2 प्रतिशत की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। इसके अलावा, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भी

3 से 4 प्रतिशत की अच्छी तेजी दर्ज की गई। हालांकि, टाइटन, टाटा स्टील, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) जैसे कुछ शेयरों में गिरावट देखने को मिली। व्यापक बाजारों की बात करें तो, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.66 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.13 प्रतिशत की हल्की गिरावट आई। सेक्टरवार प्रदर्शन में, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 3 प्रतिशत, निफ्टी बैंक में 2.5 प्रतिशत, पीएसयू बैंक में 1.2 प्रतिशत और निफ्टी आईटी में 1.3 प्रतिशत की उछाल आई। रियल एस्टेट (1.7 प्रतिशत), फाइनेंशियल सर्विसेज (1.6 प्रतिशत) और ऑटो (0.65 प्रतिशत) सेक्टर भी हरे निशान में रहे। इसके विपरीत, निफ्टी मीडिया में 1.68 प्रतिशत और निफ्टी मेटल में 0.23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 93.15 पर खुला

-पिछले दिन रुपया नौ पैसे चढ़कर 93.32 पर बंद हुआ था



मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की मजबूत लिवाली और प्रमुख प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 93.15 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के बावजूद स्थानीय मुद्रा ने मजबूती दिखाई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.25 पर खुला और फिर बढ़त हासिल करते हुए 93.15 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे की मजबूती दर्शाता है। गुरुवार को रुपया लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नौ पैसे चढ़कर 93.32 पर बंद हुआ था।

संक्षिप्त समाचार

'कुछ लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता' : जेनसन के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप, जमकर की तारीफ

शेनझेन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए जासूसी के विवाद में घिरे एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग का समर्थन किया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने प्रतिभाशाली लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हमें अपनी प्रतिभाओं का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं। राष्ट्रपति का यह समर्थन ऐसे समय में आया है, जब एनवीडिया का बोर्ड हुआंग की कंपनी में वापसी की संभावनाओं को खारिज कर चुका है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग को 'खूबसूरत महिला' बताया और कहा कि वह जासूस नहीं, बल्कि चिप खरीदने वाली एक कारोबारी हैं। वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) था। जेनसन के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा, 'हमने इस बारे में चर्चा नहीं की। हो सकता है मैंने इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया हो, क्योंकि यह बहुत बड़ी त्रासदी है। यह एक त्रासदी है। वह बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हमें अपनी प्रतिभाओं का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं।

ट्रंप-पुतिन का भव्य स्वागत, जापानी पीएम को ठंडा रिस्पॉन्स! एपेक में चीन का कूटनीतिक संदेश

बीजिंग , एजेंसी। चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। इनका भव्य स्वागत किया गया वहीं जापान की पीएम सनाए ताकाइची के प्रति रिस्पॉन्स बेहद ठंडा दिखा। ग्लोबल मीडिया में ये चर्चा का विषय है। चीन के इस कूटनीतिक व्यवहार को जापान के साथ ताइवान को लेकर जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एपेक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं का सैन्य बैंड, फूलों के गुलदस्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया तो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची को अपेक्षाकृत कम तवज्जो मिली। द गार्जियन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। ताकाइची जब शेनझेन बाओआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं तो उनके स्वागत के लिए चीन की पूर्व राजदूत झांग कियुए मौजूद थीं। उनके साथ सीमित संख्या में गार्ड ऑफ ऑनर के जवान थे। इसके विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद हवाई अड्डे पहुंचे। ट्रंप के स्वागत में सैन्य सम्मान, बच्चों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत शी जिनपिंग के करीबी वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी नेता काई छी ने किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी भव्य स्वागत मिला। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन और जापान के बीच मौजूदा तनाव की प्रमुख वजह ताइवान को लेकर ताकाइची का बयान है।

चीन : डोनाल्ड ट्रंप से मिले मार्क कार्नी, कनाडाई पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार समझौते पर की चर्चा

शेनझेन, एजेंसी। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के इतर हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा की। कार्नी ने कहा कि वे काम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। कार्नी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने शेनझेन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैठक में एक ऐसे व्यापार समझौते पर बात हुई। यह समझौता अच्छे रोजगार पैदा करेगा और सामर्थ्य को बढ़ावा देगा। साथ ही यह कनाडा की भाषाओं, संस्कृति और संप्रभुता का सम्मान करेगा। कार्नी ने यह भी बताया कि दोनों नेता संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। उन्होंने बातचीत जारी रखने की बात कही। यह बैठक दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रहे व्यापार तनाव के बीच हुई। अक्तूबर 24 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कनाडा ने व्यापार असंतुलन के जरिये अमेरिका का वर्षों से फायदा उठाया है। ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा अमेरिका की कीमत पर भारी लाभ कमा रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा वर्षों से अमेरिका से 90 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लाभ कमा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो अमेरिका के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा।

पीएम मोदी पर खरगे का आरोप...

अपनी विफलताओं के लिए कारोबारी समुदाय को जिम्मेदार ना ठहराएं

-आर्थिक उदारीकरण की जननी कांग्रेस

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में एफआईसीसीआई शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तीखा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगा मानो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता हों और वे 12 साल बाद नींद से जागे हो।

अपनी पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने दावा किया कि आर्थिक उदारीकरण की जननी कांग्रेस है और देश में सबसे अधिक दशक-औसत विकास दर कांग्रेस-यूपीए (यूपीए) के कार्यकाल के दौरान दर्ज हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी विफलताओं के लिए कारोबारी समुदाय को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी के लिए समान मौके की वकालत की है और बार-बार चेतावनी भी दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने देश के सभी संसाधन अपने 1-2 करीबी पूंजीपति मित्रों को सौंप दिए और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) तथा छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी।

भारतीय उत्पादों की ब्रैंड वैल्यू पर चिंता जताकर कांग्रेस नेता खरगे ने लिखा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी ने इनोवेशन को दबाया, विनिर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित किया और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता तथा वैश्विक ब्रांड वैल्यू को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज, न नौकरियां हैं, न ही बचत, और महंगाई अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता खरगे ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बंद कर दिया गया है, और मेक इन इंडिया को बाय फ्रॉम चाइना में बदल दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर पूंजीपतियों के एक चुनिंदा समूह को भारतीय अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक नियंत्रण हासिल करने की छूट देने का गंभीर आरोप लगाया, इस काम को वे एक आर्थिक आपदा मानते हैं।

दूसरी ओर, एफआईसीसीआई के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों की उपलब्धियां गिनाई थीं। उन्होंने कहा था कि बीते 100 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने लाइसेंस-कोटा राज, राष्ट्रीयकरण के विफल प्रयोग और



21वीं सदी में कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाने जैसे कई दौर देख चुके हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि बीते 12 वर्षों में हमारे युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के नेताओं ने इस स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती हासिल की है।

कावेरी से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की तमिलनाडु की मांग खारिज

- -सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से किया इनकार, फसल प्रभावित होने का दिया गया था हवाला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी से कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य सरकार का कहना था कि पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलें प्रभावित हो रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में राज्य में पानी की मौजूदा कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की थी। सरकार का कहना था कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से कृषि गतिविधियों पर असर पड़ रहा है और किसानों के सामने मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तमिलनाडु की ओर से कावेरी नदी से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और तमिलनाडु की मांग खारिज कर दी। कावेरी जल बंटवारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहा है। मौजूदा मामले में भी तमिलनाडु ने पानी की कमी और किसानों की परेशानी को आधार बनाकर अतिरिक्त जल छोड़ने की मांग की थी, लेकिन अदालत से राहत नहीं मिली।

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में केसीपी से जुड़ा एक उग्रवादी ढेर, कई गिरफ्तार

- मणिपुर की जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 की जा चुकी है जान

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के इंफाल वेस्ट जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक उग्रवादी को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल पटसोई पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत युरेम्बाम में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक उग्रवादी मारा गया। एक अधिकारी ने बताया कि फायरिंग में प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी के गुट से जुड़ा एक उग्रवादी मारा गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन के कई उग्रवादियों को अरेस्ट भी किया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले हाल में दिल्ली में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का वांटेड उग्रवादी पकड़ा गया था। बाद में उसे मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया था। बता दें मणिपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में मई, 2023 में घाटी में रहने वाले मैती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मणिपुर की इस जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ-ईस्ट के मणिपुर में रहने वाले मैतेई जोकि गैर-जनजातीय बहुसंख्यक समुदाय है और मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहता है, के साथ कुकी जोकि अनुसूचित जनजाति समुदाय और प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बसा है, के बीच जमीन पर अधिकार, रिजर्वेशन और पहचान से जुड़ा जातीय संघर्ष है। यह मई 2023 में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया था। मैतेई समुदाय के लोग लंबे वक्त से खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुकी समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे सरकारी नौकरियों, रिजर्वेशन और संसाधनों में उसका भाग प्रभावित हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: साइबर धोखाधड़ी में आरोपी तय नहीं कर सकता एफआईआर का स्थान

नई दिल्ली , एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाकर स्पष्ट किया कि साइबर धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों के मामलों में कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित उसके खिलाफ किस स्थान पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराएं। शीर्ष अदालत ने वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में आरोपी भूमि पटेल द्वारा विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद में दर्ज



आपराधिक मामलों को एक साथ नत्थी करने से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क दिया कि जांच में समानताएं होने को आरोपी को लाभ पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई आरोपी विभिन्न राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से नहीं रोक सकता।

शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामलों में कानून को यथासंभव सख्ती से लागू होना चाहिए। पीठ ने आरोपी को किसी भी तरह की रियायत देने के पक्ष में न होने की बात स्पष्ट कर कहा, कोई रियायत नहीं। याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वह पांच महीने से अधिक समय से अहमदाबाद केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। यह फैसला साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश है।

हाईवे से अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी तोड़फोड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर उसके पुराने आदेश को मनमानी तोड़फोड़ का आधार नहीं बनाया जा सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट संपत्तियों के स्वामित्व और अतिक्रमण की वैधता की स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले दिए गए निर्देशों का अर्थ यह नहीं है कि प्रशासन बिना उचित प्रक्रिया के किसी संपत्ति को तोड़ सकता है। संपत्ति मालिकों को अपनी आपत्ति और दावों को संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। पीठ ने संबंधित हाईकोर्ट को संपत्तियों के स्वामित्व और यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी कि संबंधित निर्माण वास्तव में वैध है या अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और संपत्ति मालिकों के अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर दिया है।

दुनिया में 2035 तक मुस्लिमों की संख्या होगी सबसे ज्यादा, इस्लाम होगा सबसे बड़ा धर्म

वाशिंगटन, डीसी , एजेंसी। प्यू रिसर्च सेंटर ने रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार, 2035 तक इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि अन्य प्रमुख धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के बच्चों की संख्या अधिक होती है। प्यू के वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ कॉनराड हैकेट ने बताया कि धर्म परिवर्तन या धार्मिक पहचान बदलने के अन्य तरीकों की तुलना में, प्रजनन दर (फर्टिलिटी रेट) कहीं अधिक बड़ा कारक है।

पाकिस्तान में हो जाएंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम : प्यू के अनुसार, 2020-2025 के दौरान मुसलमानों



में प्रजनन दर प्रति महिला 3.1 बच्चे थी, जबकि ईसाइयों में यह दर 2.5 थी। अन्य सभी समूहों की महिलाओं के लिए औसत प्रजनन दर 1.6 थी, जो 2.1 के उस स्तर से कम है जिसे किसी भी पीढ़ी के खुद को बनाए रखने (रिप्लेस करने) के लिए आवश्यक माना जाता है। प्यू के अनुसार, अगर मौजूदा रुझान जारी रहते हैं, तो 2070 तक पाकिस्तान में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी होगी। इसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का नंबर आएगा - जबकि अभी इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। प्यू के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2020 में दुनिया भर में 2.27 अरब ईसाई और 2.02 अरब मुसलमान थे। प्यू के नए अनुमानों के मुताबिक, 2035 तक मुसलमानों की संख्या 2.57 अरब और ईसाइयों की संख्या 2.52 अरब हो जाएगी। यदि मौजूदा रुझान जारी रहते हैं, तो 2070 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब से अधिक हो जाएगी, जबकि ईसाइयों की संख्या 3 अरब से थोड़ी कम होगी। इन अनुमानों में धार्मिक समूहों की आयु संरचना, प्रजनन दर, धर्म परिवर्तन और प्रवास (माइग्रेशन) के मौजूदा रुझानों को ध्यान में रखा गया है। प्यू का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों के भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाइयों का बहुमत नहीं रहेगा। प्यू के अनुसार, अभी अमेरिका की 62% आबादी ईसाई है, और 2065 तक यह आंकड़ा 50% से नीचे आ जाएगा। प्यू ने बताया कि पड़ोसी देश कनाडा में भी 2030 तक ईसाइयों की आबादी 50% से कम होने का अनुमान है। दोनों ही देशों में इस गिरावट का एक बड़ा कारण उन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी है, जो किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं।

बांग्लादेश में अवामी लीग के 'लॉकडाउन' के बीच भीषण हिंसा !



ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बृहस्पतिवार तड़के कई जगहों पर बम धमाके हुए, जबकि चटगांव में पूर्व की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को आग लगा दी गई। यह अशांति पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी अवामी लीग की ओर से बृहस्पतिवार को देशव्यापी ''लॉकडाउन के आह्वान के बाद हुई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली भंग की जा चुकी पार्टी 'अवामी लीग' द्वारा बृहस्पतिवार को देशव्यापी 'लॉकडाउन' के आह्वान के बाद पूरे देश में हिंसक झड़पें, बम धमाके और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। राजधानी ढाका में तड़के कई स्थानों पर बम विस्फोट हुए, जबकि चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस व्यापक हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बृहस्पतिवार सुबह ढाका के कई इलाकों में बम विस्फोट, तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसमें कम से कम चार लोग घायल हो गए। दूसरी ओर, चटगांव के पांचलाइश इलाके में अज्ञात उपद्रवियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के पैतृक आवास में आग लगा दी। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में यूनुस द्वारा स्थापित 'ग्रामीण बैंक' की कई शाखाओं को भी निशाना बनाकर आग लगाई गई थी। बीते दो दिनों में देश के 64 प्रशासनिक जिलों में से 28 जिलों में बम धमाके और वाहनों को फूंकने की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार रात ढाका में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक कार्यकर्ताओं- जिन्हें प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़ा माना जा रहा है- ने अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला कर आग लगा दी। इससे पहले बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित ग्रामीण बैंक की कई शाखाओं को भी आग के हवाले कर दिया गया था। अखबारों की खबरों के अनुसार, बुधवार रात प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला किया या उन्हें आग लगा दी। माना जा रहा है कि ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़े थे।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा: हकीम जेफ्रीज बन सकते हैं पहले अश्वेत स्पीकर, डेमोक्रेट्स ने लगाई नाम पर मुहर

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी ने हकीम जेफ्रीज को नए कांग्रेस सत्र के लिए अपना नेता चुन लिया है। इसके साथ ही उनके अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पहले अश्वेत स्पीकर बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जनवरी में नए कांग्रेस सत्र की शुरुआत पर सदन में होने वाला औपचारिक मतदान इस पद पर उनकी नियुक्ति का अंतिम चरण होगा। मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के करीब दो सप्ताह बाद पार्टी ने जेफ्रीज के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि, पार्टी के कुछ नवनिर्वाचित प्रगतिशील सांसदों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। वे समर्थन के बदले नीतिगत मुद्दों पर ठोस आश्वासन चाहते थे।

गोपनीय मतदान में 11 सांसदों ने किया विरोध : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के गोपनीय मतदान में केवल 11 डेमोक्रेटिक सांसदों ने जेफ्रीज के खिलाफ वोट दिया। इससे जनवरी में उनके स्पीकर चुने जाने की संभावना मजबूत हुई है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध करने वाले सांसद भी सदन में अंतिम मतदान के दौरान उनका समर्थन कर सकते हैं।

नामांकन मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जेफ्रीज ने कहा कि अमेरिकी जनता बड़े और बुनियादी बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति स्वीकार्य नहीं है और डेमोक्रेटिक



पार्टी लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रगतिशील सांसदों ने रखीं नीतिगत शर्तें : जेफ्रीज का विरोध करने वाले सात नवनिर्वाचित प्रगतिशील डेमोक्रेटिक सांसदों ने कहा कि वे मेडिकेयर फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना पर मतदान कराने और गाजा में कथित नरसंहार खत्म करने जैसे मुद्दों पर प्रतिबद्धता चाहते हैं। इन सांसदों में न्यूयॉर्क की डारियालिजा एविला शेवेलियर, न्यू जर्सी के एडम हमावी, टेक्सास के फ्रेडरिक हेन्स, कोलोराडो की मेलाट किरोस, मिशिगन के डोनावन मैकिनी और पेंसिल्वेनिया के क्रिस रैब के साथ न्यूयॉर्क की क्लेयर वाल्डेज शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सांसद डॉन लियोनार्ड ने भी जेफ्रीज के नामांकन के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने कहा कि वह चुनावी चंदे से जुड़े नियमों में सुधार और इजराइल को अमेरिकी सहायता रोकने के मुद्दे पर मतदान कराने का आश्वासन चाहते हैं। लियोनार्ड के मुताबिक, जब तक इन मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं मिलती, तब तक उनका समर्थन नहीं होगा। जेफ्रीज ने पार्टी के भीतर विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स का काम मैगा कट्टरपंथ का मुकाबला करना है, न कि आपस में लड़ना।

कई गुटों से जेफ्रीज ने की बातचीत : नामांकन से पहले जेफ्रीज ने उन नवनिर्वाचित सांसदों से आमने-सामने बातचीत की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके समर्थन का ऐलान नहीं किया था। इनमें से कई सांसद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े थे। उन्होंने पार्टी के अलग-अलग गुटों से भी संपर्क किया। इनमें सेंटरिस्ट सांसद, न्यू डेमोक्रेट कोएलिशन, ब्लू डॉग कॉकस और कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस शामिल हैं। जेफ्रीज को वरिष्ठ सांसद जिम क्लाइबर्न का भी मजबूत समर्थन मिला। क्लाइबर्न कांग्रेसनल ब्लैक कॉकस के वरिष्ठ सदस्यों में शामिल हैं। उन्होंने पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि हकीम सुर्खियों के बजाय ठोस प्रगति में रुचि रखते हैं। जेफ्रीज ने शुक्रवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के कई प्रमुख प्रस्तावों का समर्थन किया। इनमें मेडिकेयर के लिए पात्रता की उम्र घटाना, बच्चों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए नई योजना शुरू करना और मेडिकेयर में सुनने, दांतों और आंखों से जुड़ी सेवाओं को शामिल करना शामिल है।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कंालटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com